राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई,उत्तरप्रदेश,बिहार,राजस्थान,मध्यप्रदेश,उतरांचल,उतराखंड,दिल्ली,हरियाणा में प्रसारीत

क्रांति समय
SURESH MAURYA
(Chief Editor)
M. 98791 41480
Working. off.: STPI-SURAT, GUJARAT-395023
(Software Technology Park of India, Surat.
www.krantisamay.com
www.krantisamay.in
krantisamay@gmail.com

सुरत–गुजरात,संस्करण शुक्रवार,१२मार्च २०२१ वर्ष–४, अंक –४८ पृष्ठ–०८ मूल्य–०१रूपये

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

अमेरिका को भी सिरदर्द लग रहा चीन, कहा- 21वीं सदी में बन गया है सबसे बड़ा रणनीतिक खतरा

नई दिल्ली। चीन सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के सुपरपावर अमेरिका के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन के एक शीर्ष कमांडर एडमिरल फिल डेविडसन ने अपने सांसदों को बताया कि चीन ने 21वीं सदी में सबसे बड़ा दीर्घकालिक रणनीतिक खतरा पैदा कर दिया है। पेंटागन ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के लिए बीजिंग के बहुत ही खतरनाक दृष्टिकोण में भ्रष्ट, सह-ऑप्ट सरकारों, व्यवसायों के लिए पार्टी का पूरा प्रयास शामिल है। डेविडसन ने कहा कि जैसा कि चीन पीएलए का आकार बढ़ा रहा है और अपनी संयुक्त क्षमताओं को आगे बढ़ा रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए इंडो-पैसिफिक में सैन्य संतुलन अधिक प्रतिकूल होता जा रहा है। यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल फिल डेविडसन ने हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सदस्यों को बताया कि 21 वीं सदी में सबसे बड़ा दीर्घकालिक रणनीतिक खतरा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, हमारी स्वतंत्र और खुली दृष्टि से उलट आंतरिक उत्पीड़न के माध्यम से एक बंद और सत्तावादी व्यवस्था को बढ़ावा देती है, साथ ही चीन बाहरी आक्रामकता को बढ़ावा देता है। बता दें कमांडर ने बुधवार को भारत चीन विवाद को लेकर यह भी कहा था कि चीन अभी भी एलएसी पर कई हिस्सों से पीछे नहीं हटा है। ये वो जगह है जहां चीन ने सीमा पर विवाद के दौरान कब्जा कर लिया था यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल फिलिप्स डेविडसन ने कांग्रेस की सुनवाई के दौरान सीनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सदस्यों को ये जानकारी दी। डेविडसन ने अमेरिका में सीनेट की सुनवाई के दौरान टिप्पणी में कहा, ÷पीएलए ने अभी तक सीमा विवाद के बाद घेरे गए कई आगे के पोस्ट से अपने कदम पीछे नहीं लिए हैं। हालांकि चीनी और भारतीय सेना ने लद्दाख में पैंगोंग त्सो के आसपास विवादित सीमा के कुछ हिस्सों से अपने-अपने सैनिकों को वापस ले लिया है।

देशभर में महाशिवरात्रि की धूम, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने दी बधाई

महाशिवरात्रि के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई बड़ी हस्तियों ने लोगों को शुभकामनाएं दीं। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में हर हर महादेव लिखा।

नई दिल्ली। पूरे देश में शिव और शक्ति के मिलन का पावन पर्व महाशिवरात्रि मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत जानी-मानी हस्तियों ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। मोदी ने एक ट्वीट में लिखा, 'देशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं। हर-हर महादेव!' कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैलास की तस्वीर ट्वीट करते हुए महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दीं।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट में लिखा, 'महाशिवरात्रि के पुनीत अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। देवी पार्वती और भगवान शिव के विवाह के पावन स्मरण स्वरुप मनाया जाने वाला यह उत्सव सम्पूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी हो।' दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी महाशिवरात्रि पर मंगलकामनाओं का पोस्ट किया।

केजरीवाल ने कहा, 'सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे।'

कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने बधाई देते हुए लिखा, 'महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

इस अवसर पर मेरी कामना है कि भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर बनी रहे।' केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पोस्ट शेयर किया और लिखा, 'समस्त देशवासियों को महाशिवरात्रि क

पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन दिन पर भगवान शिव एवं माँ आदिशक्ति से हम सभी के जीवन में सुख, शांति एवं उन्नति के लिए प्रार्थना करती हूँ।'

गुजरात के सीएम विजय रुपानी ने सोमनाथ को याद करते हुए लोगों को बधाई दी और कहा, देवाधिदेव महादेव की आराधना के पवित्र पर्व महाशिवरात्रि की सभी को हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएँ। भगवान शिव और माता पार्वती के आशीष से सम्पूर्ण विश्व में शांति, सद्भावना एवं समृद्धि का वास हो, यही प्रार्थना है। ? नमः शिवाय जय सोमनाथ।

क्यों खास है यह शिवरात्रि?

बता दें कि आज से ही पहले शाही स्नान के साथ हरिद्वार कुंभ की भी भव्य शुरुआत हो गई है। इस मौके पर हर की पौड़ी पर सजावट की गई और दूर-दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई।

दिल्ली की अवैध कॉलोनियां होंगी नियमित, संसद में बिल पास, लाखों लोगों को होगा फायदा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने से संबंधित संशोधन विधेयक कोसंसद ने मंजूरी प्रदान कर दी। इसके माध्यम से संबंधित कानून की समय सीमा को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को पहले मंजूरी प्रदान कर दी थी और बुधवार को लोकसभा में यह पारित हो गया। केंद्रीय कृषि कानूनों के मुद्दे पर लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों की नारेबाजी के बीच निचले सदन में चर्चा के बाद राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कानून (विशेष प्रविधान) दूसरा (संशोधन) अधिनियम-2021 विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया।

पुरी ने कहा, पूर्व की सरकारों ने कॉलोनियों को नियमित करने में घोर लापरवाही बरती

विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने दिल्ली की इन कॉलोनियों को नियमित करने में घोर लापरवाही बरती। पुरी ने कहा कि जनता के बीच यह धारणा है कि कुछ राजनीतिक दलों के सत्ता में रहते हुए कॉलोनियों को नियमित करने में विलंब किया गया। उन्होंने किसी दल का नाम लिए बगैर कहा कि इससे पहले किसी सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। पुरी ने बताया कि अगर कोरोना महामारी नहीं आती तो अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का काम काफी हद तक पूरा हो गया होता। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। वर्ष 2011 का संबंधित कानून पिछले साल 31 दिसंबर तक वैध था।

दिल्ली सरकार ने कोई काम नहीं किया- मीनाक्षी लेखी

इससे पहले, विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा की मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वह 2047 तक दिल्ली को सिंगापुर बनाना चाहते हैं। ये लोग चुनावों से पहले इसी तरह की बातें करते हैं। लेकिन समय रहते कोई कदम नहीं उठाया जिस कारण ये कानून लाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए दिल्ली सरकार ने कोई काम नहीं किया।

आगरा में दर्दनाक

स्कॉर्पियो और कंटेनर की जोरदार टक्कर में 9 लोगों की मौत

आगरा। उत्तर प्रदेश के आगरा में नेशनल हाईवे-19 पर गुरुवार तड़के सुबह बड़ा हादसा हो गया। एत्मादपुर की ओर से आ रही स्कॉर्पियो डिवाइडर पर चढ़कर गलत साइड आ गई और कंटेनर से जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। जबकि तीन को गंभीर हालत में एसएन इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह हादसा तड़के सुबह 5.15 बजे हादसा हुआ। एत्मादपुर की ओर से आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ने के बाद रांग साइड पहुंच गई। इसी बीच रामबाग की ओर से कंटेनर आ गया और दोनों में जोरदार टक्कर हो गई। स्कॉर्पियो में टक्कर

मारने के बाद कंटेनर छोड़कर चालक और क्लीनर मौके से फरार गए। हादसे में स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त हो गई और इसमें सवार लोग फंस गए। लोगों ने स्कॉर्पियो में फंसे चार घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचा दिया। मौके पर पुलिस के पहुंचने के बाद स्कॉर्पियो की बॉडी तोड़कर अन्य लोगों को निकालने की कोशिश की गई। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद स्कॉर्पियो में फंसे अन्य लोग निकल सके। स्कॉर्पियो में चालक समेत 12 लोग सवार बताए जा रहे हैं। इनमें से आठ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की सांसें अस्पताल पहुंचने पर थम गई। तीन को एसएन इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है।स्कॉर्पियो का नंबर जेएच 13 डी 5029 है।पुलिस गाड़ी नंबर के आधार पर शिनाख्त के प्रयास कर रही है।हाईवे पर हादसे के बाद कई किमी तक जाम लग गया।हाईवे से कंटेनर और क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो को हटवा रही है।

संपत्ति उत्तराधिकार के नियम सबके लिए समान क्यों नहीं, SC का केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से एक समान उत्तराधिकार और विरासत कानून की मांग वाली याचिका पर प्रतिक्रिया मांगी, जो जेंडर और रिलीजन न्यूट्रल हैं। भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि उत्तराधिकार और विरासत में समान कानून न्याय, समानता और महिलाओं की गरिमा को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने आज तक इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है। इस याचिका में

नियमों को लिंग या धर्म से तटस्थ बनाने का अनुरोध किया गया है। बता दें कि सभी नागरिकों के लिए समान नियम कानून लागू करने की मांग वाली यह पांचवी याचिका है जिस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इससे पहले पिछले साल 16 दिसंबर को सभी नागरिकों के लिए तलाक और भरण पोषण के नियम एक समान करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी हुआ था।

पैर में प्लास्टर, बुखार और सीने में दर्द...ममता बनर्जी को आईं गंभीर चोटें, डॉक्टरों ने बताया दीदी का हाल

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान कथित रूप से अपनी कार के दरवाजे को धक्का दिए जाने की वजह से चोटिल हो गईं। घटना शाम को उस वक्त घटी, जब ममता रियापारा में एक मंदिर के बाहर खड़ी थीं। बुधवार की देर रात ममता बनर्जी की प्राथमिक मेडिकल टेस्ट की प्रांरभिक रिपोर्ट आई, जिसमें उन्हें कई जगहों पर चोटें आईं हैं और एक पैर में प्लास्टर भी हुआ है। सरकारी एसएसकेएम अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर ने कहा कि ममता बनर्जी पर किए गए प्राथमिक चिकित्सा परीक्षण में उनके बाएं टखने और पैर की हड्डियों में

गंभीर चोटों का पता चला है। साथ ही दाहिने कंधे, गर्दन और कलाई में भी चोटें आई हैं।

उन्होंने कहा कि अस्पताल में ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में कथित हमले के बाद सीने में दर्द और सांस फूलने की शिकायत की है। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें अगले 48 घंटों के लिए निगरानी में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख को हल्का बुखार है और बांगुर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेस में एमआरआई के तुरंत बाद अस्पताल के वीवीआईपी वुडबर्न ब्लॉक में उन्हें विशेष वार्ड में भेज दिया गया है।

ममता बनर्जी का इलाज कर रही टीम के एक डॉक्टर ने कहा, %हम अगले 48 घंटों तक उसे निगरानी में रखेंगे। इसके लिए और भी कई परीक्षण करने होंगे और उनकी स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद हम उनके अगले उपचार के बारे में फैसला करेंगे। बुधवार की रात को पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम से वहां ले जाते समय डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री का एक्स-रे किया।

राज्य सरकार ने बनर्जी के उपचार के लिए पांच वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम बनायी है। बनर्जी पर शाम को चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम में कथित रूप से हमला हुआ। एसएसकेएम अस्पताल के वुडबर्न ब्लॉक के 12.5 विशेष केबिन में उनका इलाज चल रहा है। ममता बनर्जी का इलाज कर रही टीम में एक कार्डियोलॉजिस्ट, एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, एक सामान्य सर्जरी डॉक्टर, एक ऑर्थोपेडिस्ट और एक दवा डॉक्टर है। बता दें कि चुनाव आयोग ने ममता पर हमला मामले में रिपोर्ट तलब की है।

कोरोना काल में यूपी ने मिटाई दूसरे देशों के करोड़ों लोगों की भूख

लखनऊ। कोरोना महामारी में केंद्र सरकार की मदद और योगी सरकार के कुशल प्रबंधन के चलते न केवल यूपी लौटे श्रमिकों-गरीबों को मुफ्त में अनाज वितरण की व्यवस्था की गई बल्कि चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ईरान, यूके, इटली और सऊदी अरब जैसे देशों के करोड़ों लोगों की भूख शांत करने में भी यूपी अन्य बहुत से राज्यों से आगे रहा। राज्य ने पहले से कई गुना गेहूं, चावल, दाल, खाद्य तेल, मीट, चीनी, खांड़, दुग्ध उत्पाद, तंबाकू उत्पाद, फार्मास्युटिकल जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुएं विदेशों को भेजीं। खाद्य-पदार्थ, दवा, तंबाकू जैसी वस्तुओं का निर्यात ग्राफ कोरोना कालखंड में तेजी से बढ़ा है। 10 माह के तुलनात्मक आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना काल में गेहूं साढ़े पांच गुना, दाल दो गुने से अधिक, वनस्पति तेल डेढ़ गुना, अन्य अनाज डेढ़ गुना, प्रोसेस्ड मीट साढ़े चार गुना अधिक निर्यात किया गया। यह आंकड़े अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के बीच के हैं।

खाद्य पदार्थों के निर्यात से राज्य की अर्थव्यवस्था को बल मिला

अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के बीच की अवधि कोरोना महामारी के लिहाज से सबसे अधिक भयावह रहा। विश्व के अधिकांश देश लॉकडाउन और तमाम प्रतिबंधों के दौर से गुजर रहे थे। कारोबार ठप से पड़े थे। निर्यात पर भी प्रतिकूल असर पड़ा था। इस दौर में उत्तर प्रदेश का निर्यात बहुत प्रभावित नहीं हुआ। अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 की अवधि के मुकाबले अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के बीच की अवधि में यूपी के निर्यात

में महज 4.75 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इस अवधि में कुल निर्यात में 8.67 फीसदी की कमी आई।

महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली के मुकाबले निर्यात की स्थिति बेहतर

इसी अवधि में बड़े निर्यातक राज्यों में गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, राजस्थान और मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो यूपी की स्थिति अन्य राज्यों के मुकाबले निर्यात में बेहतर रही है। महाराष्ट्र में 13.64 फीसदी, तमिलनाडु में 14.60, कर्नाटक 11.41, पश्चिम बंगाल 11.00, केरल 62.92, बिहार 14.07, जम्मू-कश्मीर 17.58 और दिल्ली के कुल निर्यात में 25.12 में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश की इस बेहतर स्थिति के लिए राज्य सरकार ने दूतावासों के माध्यम से लगातार विदेशों से संपर्क रखा। सरकार द्वारा निर्यात में दी गई सुविधाओं का लाभ निर्यात बढ़ाने में हुआ। अनुमान है कि 31 मार्च 2021 तक राज्य का कुल निर्यात पिछले वित्तीय वर्ष के बराबर यानी 1.20 लाख करोड़ पहुंच जाएगा।

इन देशों को किया गया निर्यात

बासमती चावल- ईरान, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यमन, यूएसए, कनाडा, साउथ अफ्रीका, कतर, इटली, सऊदी अरब

सामान्य चावल- नेपाल, सोमालिया, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, चीन, टोगो, यमन, यूएसए

गेहूं- बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर

दाल- नेपाल, यूएसए, यूएई, इराक, यूके, सिंगापुर, फिलिपींस, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन

तंबाकू- मलेशिया, नेपाल, सऊदी अरब, यूएएई, थाईलैंड, अफगानिस्तान, म्यांमार, लिथुवानिया, यूएसए, जर्मनी, ईरान, यमन, यूक्रेन

वनस्पति तेल- यूएसए, कनाडा, नेपाल, यूके, सऊदी अरब, जार्डन, आस्ट्रेलिया, यूएई, मॉरीशस, बांग्लादेश

चीनी- इंडोनेशिया, ईरान, नेपाल, अफगानिस्तान, चीन, सोमालिया, लीबिया, यमन, न्यूजीलैंड, श्रीलंका

प्रॉसेस्ड फ्रूट व जूस- नेपाल, यूक्रेन, म्यांमार, यूएई, थाईलैंड, यूएसए, यूके, भूटान, कतर, बहरीन

बफेलो मीट- हांगकांग, वियतनाम, कैरो, इंडोनेशिया, मलेशिया, इराक, सऊदी अरब, यूएई, फिलिपींस, अल्जीरिया

प्रासेस्ड मीट- हांगकांग, नेपाल, कतर, यूएई

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संपादकीय

हरियाणा का संकट

हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव का गिर जाना जितना स्वाभाविक है, उतना ही सीखने योग्य भी। बुधवार को पेश अविश्वास प्रस्ताव पर बाकायदे बहस हुई, पर हरेक पार्टी ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया था। ऐसे में, कांग्रेस को सरकार में शामिल जिस जननायक जनता पार्टी (जजपा) से उम्मीद थी, उसके विधायकों के हाथ बंध गए। बाहर नाराजगी का इजहार करने वाले जजपा विधायक भी पार्टी व्हिप के खिलाफ जाने की नहीं सोच सकते थे। वैसे तो कांग्रेस को भी अंदाजा था कि क्या होने वाला है। कांग्रेस ने पहले की कह दिया था कि उसका मकसद भाजपा और जजपा को बेनकाब करना है। चूंकि अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के बाद सरकार के खिलाफ भाषण का मौका मिलता है, तो कांग्रेस ने लाभ उठाया। विधानसभा में मुख्यमंत्री खट्टर के भाषण से यह साफ हो गया कि कांग्रेस ने सत्ता पक्ष की नींद उड़ा रखी है। नैतिकता के पैमाने पर देखें, तो कांग्रेस ने जो किया, वह सदन के समय की बर्बादी थी, लेकिन अगर राजनीतिक नजरिए से देखें, तो इसमें कोई नई बात नहीं। किसी भी विपक्षी पार्टी को सुविधा हासिल है कि वह सरकार की कमजोरी या ताकत को समय-समय पर परखे। पंजाब की राजनीति में जहां अभी सुकून का आलम है, वहीं हरियाणा में खासतौर पर जमीनी स्तर से लेकर विधानसभा तक तनाव व्याप्त है। खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कृषि कानूनों और किसान आंदोलन के आधार पर ही लाया गया था। दरअसल, आंदोलनरत किसान जगह-जगह सत्ताधारी नेताओं को घेरने लगे हैं, जिससे कुछ इलाकों में नेताओं को जाने में परेशानी होने लगी है। वैसे तो किसान आंदोलन को देशव्यापी बताया जा रहा है, पर इसमें कोई शक नहीं कि हरियाणा के सत्ताधारी नेताओं पर इसका सर्वाधिक दबाव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति और जन-प्रतिनिधि भी तनावग्रस्त हैं, पर अगर कोई पूरा राज्य आंदोलन की आंच झेल रहा है, तो वह हरियाणा है। यहां सत्ता में रहते कांग्रेस ने अनुबंध खेती का प्रावधान किया था, पर अब वह कृषि कानूनों के खिलाफ है। भाजपा जहां कृषि कानूनों के पक्ष में है, वहीं सत्ता में शामिल जजपा विधायक रह-रहकर असंतोष जताते आए हैं और विपक्ष को सरकार की ताकत पर संदेह के मौके मिलते रहे हैं। हालांकि, अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर कांग्रेस के 30 में से 25 विधायकों के ही हस्ताक्षर थे। वह खुद एकमत नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव भले गिर गया, मगर हरियाणा में सत्ताधारी नेताओं पर तब तक संकट मंडराएगा, जब तक आंदोलन जारी है। इसकी आंच पर राजनीतिक रोटियां सेंकने की प्रशंसा भला कौन करेगा? आंदोलन का लाभ आज भले कोई पार्टी तात्कालिक रूप से ले ले, पर दूरगामी रूप से किसानों के सवाल सभी को परेशान करेंगे। किसानों के सवालों के जवाब उतने आसान होते, तो आंदोलन इतना लंबा न खिंचता। जहां तक राज्यों की राजनीति का प्रश्न है, तो वह भी जटिल ही है। किसान आंदोलन के समय ही पंजाब में जहां भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है, वहीं गुजरात में वह बड़ी विजेता बनकर सामने आई है। मतलब, किसी भी एक पार्टी को पूरा फायदा या नुकसान नहीं हो रहा है। यह संकेत है कि देर-सबेर शायद सभी को मिलकर समाधान के प्रयास करने पड़ेंगे।

आज के ट्वीट

नमन

देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन। महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक चेतना में उनके उल्लेखनीय योगदानों से भारतवर्ष हमेशा उनका ऋणी रहेगा।

-- पी पी चोधरी

विकास गाथा और नौकरियों में आरक्षण

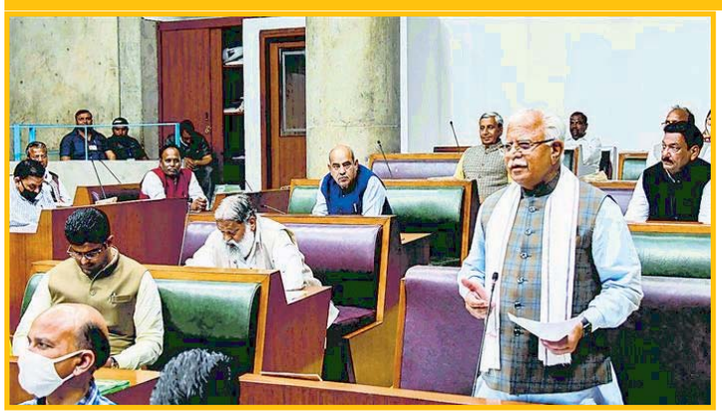

अनिंदयो चक्रवर्ती

हरियाणा ने एक नया कानून बनाया है। इसके मुताबिक यदि किसी निजी कंपनी में 50 हजार रुपये तक की 4 नौकरियां निकलती हैं तो 3 रिक्तियां स्थानीय कामगारों से भरनी पड़ेंगी। इस निर्णय की काफी विवेचना हुई है, अधिकांशतः जानकार इसके विरुद्ध हैं। लेकिन मुझे इसमें जो बात मजेदार लगी, वह यह कि हरियाणा की भाजपा-नीत सरकार का यह फैसला केंद्र की मोदी सरकार की नीति से अलग राह पर जाता है। पिछले तीन दशकों में नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें आम चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला है। वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी को मिली ऐसी सफलता के बाद सिर्फ उन्होंने यह कर दिखाया है, जबकि इस दौरान बनी तमाम केंद्रीय सरकारें क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करके ही सत्ता में बनी रह सकी थीं। गोकि, इस व्यवस्था ने यह सुनिश्चित किया था कि देश का संघीय ढांचा बरकरार रहे। वास्तव में 1996 से 2009 के बीच चले गठबंधन-काल में किसी एक दल को 200 से ज्यादा लोकसभा सीटें नहीं मिली थीं, लिहाजा केंद्र के नीति-निर्धारण फैसलों में राज्य सरकारों की सहमति काफी महत्वपूर्ण बन गई थी। चूंकि वर्ष 2014 के बाद लोकसभा में एक ही दल का भारी दबदबा है, तिस पर ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकारें थीं, इस स्थिति ने प्रधानमंत्री मोदी को मौका दिया कि संघीय ढांचा कमजोर कर शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में इकट्ठी की जाएं। वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) इसका एक उदाहरण है, 'एक देश-एक कराधान' का नारा लगाकर राज्य सरकारों से अपनी-अपनी कर-नीति निर्धारण का हक छीन लिया गया। सत्ता में केंद्रीकरण को और आगे बढ़ाने का ताजा उदाहरण नए कृषि-कानून हैं। मोदी सरकार की 'चुनाव नीत-आर्थिक नीति' राज्यों की सार्वभौमिकता की एवज पर है। अब हो यह रहा है कि केंद्र सरकार को मिलने वाले अतिरिक्त कर का बहुत बड़ा हिस्सा थोपे गए सेस और सरचार्ज से आता है, जिसे वह राज्यों से बांटने की जरूरत नहीं समझता। यह व्यवहार जीएसटी लागू करते वक्त किए गए उस वादे के खिलाफ है कि सूबों की राजस्व हानि की भरपाई की जाएगी। समाज के सबसे वंचित तबके को दी जाने वाली राहतें और सहायता योजनाएं मसलन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री वंदना योजना इत्यादि का लाभ भले ही राज्य सरकारों के माध्यम से पहुंचाया जाता है, लेकिन इनका असल मकसद मतदाता के मन में मोदी की छवि बैठाना है। जबकि ठीक इसी समय आर्थिक मोर्चे पर केंद्र सरकार को मिली अनेकानेक विफलताओं का ठीकरा राज्य सरकारों के सिर पर फोड़ दिया जाता है। इसलिए हमें देखने को मिला है कि जिन राज्यों में भाजपा को लोकसभा चुनाव में मोदी के नाम पर भारी मत मिले थे, वहां वह विधानसभा चुनावों में अपनी सरकार बनाने में विफल रही है। बेरोजगारी एक ऐसा विषय है, जिसके लिए मतदाता राज्य सरकार को उत्तरदाई ठहराते हैं। वर्ष 2019 में आए चुनाव-पूर्वानुमानों ने बताया था कि हालांकि लोकसभा चुनाव में रोजगार की कमी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था। फिर भी जिन लोगों को सर्वे में शामिल किया गया था, उनमें अधिकांश का मत था कि इसके लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। इससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तनाव बने रहने का सिलसिला चल निकला और इसमें राजग शासित राज्य भी शामिल हैं। जब बात आर्थिक नीति की आए तो आज की तारीख में राज्यों के पास स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति लगभग नगण्य है, तथापि अर्थव्यवस्था खराब होने का दोष उनको सहना पड़ रहा है। कोविड लॉकडाउन के दौरान चंद राज्य सरकारों को भुजाएं फड़फड़ाते देखा था, जिन्होंने पलायन करते मजदूरों को अपनी सीमाओं पर रोकने की कोशिश की थी या एक निर्धारित संख्या से ज्यादा घुसने से मना किया था, यहां तक कि अपने यहां स्थानीय लोगों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सहायता 'बाहरी' लोगों को न देने की बात भी कही थी। जबकि असल में वे कहना चाह रहे थे कि हमारा काम अपने लोगों को देखना है न कि उनको जो बाहर से आए हैं। यह 'बाहरी' का ठप्पा वैसे भी देशभर में सदा राजनीतिक लाभ लेने का एक तरीका रहा है। चाहे यह महाराष्ट्र हो या कर्नाटक, असम या फिर अब पश्चिम बंगाल। इस अवयव को संघीय सरकार द्वारा शक्तियों का केंद्रीकरण करना और राज्य सरकार द्वारा भाषाई उप-राष्ट्रवाद को उभारकर संप्रभुता पाने की स्थाई फितरत के तौर देखा जाना चाहिए। स्थानीय लोगों को लगता है 'अपनी भूमि' पर निकली नौकरियां या स्रोतों पर पहला नैसर्गिक हक उनका है और जब देखते हैं बाहरी लोग कम वेतन पर काम करने को राजी होकर उनका अवसर मार रहे हैं तो खीझ उठते हैं। इसलिए उप-राष्ट्रवाद की यह भावना क्षेत्रीय रोजगार और शिक्षा में बनने वाले अवसरों के वक्त तो उफान ले लेती है, लेकिन जब बात केंद्रीय सरकार पर आए तो यह मुद्दा गौण हो जाता है। अतएव, 'एक देश-एक मंडी' का नारा लगाने वाली मोदी सरकार के तमाम दावों के बावजूद भाजपा-शासित प्रदेशों की सरकारों को भी अपने राज्य के रोजगार अभिलाषियों के स्वार्थ की पूर्ति करनी पड़ती है। आखिरकार जब विधानसभा में वोट डालने की बारी आएगी तो हो सकता है प्रवासी मजदूर तो छुट्टी लेकर अपने सूबे में वोट डालने चला जाए और पीछे छूटा कुंठित बेरोजगार स्थानीय मतदाता तब वोट के जरिए बदला निकालने की फिराक में होगा। कोविड महामारी की वजह से भारतीय आर्थिकी में बनी मंदी से भी पहले यानी सितंबर-दिसंबर 2019 के केंद्रीय आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में रोजगार ताकने वालों की संख्या 24 प्रतिशत थी। यह गिनती उस वक्त और भी चिंताजनक बन जाती है, जब पाते हैं कि 20-24 वर्ष के युवा वर्ग में बेरोजगारी का स्तर संख्या चौंकाने वाला 74 फीसदी है। यह हालत लॉकडाउन से उबरते भारत में और ज्यादा भयावह हो गई जब सितंबर-दिसंबर 2020 के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में रोजगार अभिलाषियों की गिनती 33 प्रतिशत तो 20-24 आयुवर्ग के बेरोजगार 85 फीसदी हो गए। इसका मतलब प्रत्येक 6 युवाओं में केवल 1 के पास नौकरी है। इस समस्या को हल करने का एक तरीका होता कि नौकरियां ज्यादा संख्या में पैदा की जाएं और सरकारी-अर्धसरकारी संस्थानों में खाली पड़े पद भरे जाएं। चूंकि राज्य सरकारों के पल्ले पैसा नहीं है और अपने वित्तीय घाटे को काबू में रखने की खातिर केंद्रीय सरकार राज्यों के हिस्से का पैसा कम दे रही है तो ज्यादा संख्या में सरकारी नौकरियां बनाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इस स्थिति में भाजपा-जजपा गठबंधन के पास रोजगार में क्षेत्रवाद का पत्ता चलने के सिवा कोई चारा नहीं था। उनके लिए गुरुग्राम की चुंधियाती गगनचुंबी इमारतें एवं चमचमाते दफ्तर और विशालकाय उद्योग किस काम के, यदि हरियाणा राज्य के लोगों को रोजगार न मिल पाए? उधर, उद्योग संगठन एवं आर्थिक मामलों के जानकार स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण बनाने वाले इस नए कानून की आलोचना कर रहे हैं। इस नए कानून के अनेक प्रावधान इंस्पेक्टर राज की वापसी का संकेत हैं। लागू किए गए नए नियमों की अक्षरशः पालना करने की वजह से व्यापार-लागत बढ़ जाएगी। इस बात का पूरा डर है कि कुछ कंपनियां हरियाणा से पलायन कर जाएंगी। कुछ माहिरों का कहना है कि नया कानून हरियाणा के विकास की प्रभावशाली गाथा का पटाक्षेप बनकर आया है। लेकिन राजनेता बखूबी जानते हैं कि जब चुनाव आएगा तो मतदाता में प्रभाव विकास-गाथा का नहीं बल्कि उनका पड़ेगा जो यह सिद्ध कर देगें कि हमने आपको रोजगार दिलवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया।

लेखक आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक हैं।

ज्ञान गंगा

स्वभाव और संस्कार

श्रीराम शर्मा आचार्य

जैसा मनुष्य का स्वभाव होता है उसी के अनुरूप उसकी मनोदशा बनती रहती है और जब वही आदत अपने जीवन का अंग बन जाती है तो उसे संस्कार मान लेते हैं। शराब पीना प्रारम्भ में एक छोटी सी आदत दिखती है किन्तु जब वही आदत गहराई तक जक जाती है, तो शराब के सम्बन्ध में अनेकों प्रकार की विचार रेखायें मस्तिष्क में बनती चली जाती हैं, जो एक स्थिति समाप्त हो जाने पर भी प्रेरणा के रूप में मस्तिष्क में उठा करती हैं। जैसे कोई कामुक प्रवृत्ति का मनुष्य स्वास्थ्य सुधार या किसी अन्य कारण से प्रभावित होकर ब्रह्मचर्य रहना चाहता है। इसके लिए वह तरह-तरह की योजनाएं और कार्यक्रम भी बनाता है तो भी उसके पूर्व जीवन के कामुक विचार उठने से रुकते नहीं और वह न चाहते हुए भी उस प्रकार के विचारों और प्रभाव से टकराता रहता है। यह संस्कार जैसे भी बन जाते है वैसा ही मनुष्य का व्यवहार होगा। यहां यह न समझना चाहिए कि यदि पुराने संस्कार बुरे पड़ गये हैं, विचारों में केवल हीनता भरी है, तो मनुष्य सद्व्यवहार नहीं कर सकता। यदि पूर्व जीवन के कुसंस्कार जीवन सुधार में किसी प्रकार का रोड़ा अटकाते है तो भी हार नहीं माननी है। चूंकि अब तक अच्छे कर्म नहीं किए थे इसलिये यह पुराने कुविचार परेशान करते हैं किन्तु यदि अब विचार और व्यवहार में अच्छाइयों का समावेश करते हैं तो यही एक दिन हमारे लिए शुभ संस्कार बन जाएगा। तब यदि कुकर्मो की ओर बढ़ना चाहेंगे तो एक जबर्दस्त प्रेरणा अन्तःकरण में उठेगी और हमें बुरे रास्ते में भटकने से बचा लेगी। महर्षि वाल्मीकि, सन्त तुलसीदास, भिक्षु अंगुलिमाल, गणिका, अजामिल आदि अनेकों कुसंस्कारों में ग्रसित व्यक्ति भी जब सन्मार्ग पर चलने लगे तो उनका जीवन पुण्यमय, प्रकाशमय बन गया। मनुष्य संस्कारों का गुलाम हो जाए, अपने स्वभाव में परिवर्तन न कर सके, यह असम्भव नहीं है, यह आसान भी है और कई लोगों ने ऐसा किया भी है। मनुष्य के विचार गीली मिट्टी और संस्कार उस मिट्टी से बने बर्तन के समान होते हैं। पिछले कुसंस्कारों का बड़ा तोड़कर नये विचारों की मिट्टी से नव-जीवन घट का निर्माण कर सकते हैं। इसमें राई-रत्ती भर भी सन्देह न करना चाहिए।

आज का राशिफल

मेष संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। व्यावसायिक समस्याएं रहेंगी। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे। जीविका की दिशा में प्रगति होगी। रोजी रोजगार की दिशा में सफलता मिलेगी।

वृषभ पारिवारिक जनों के साथ सुखद समाचार मिलेगा। जारी प्रयास सफल होंगे। खानपान में संयम रखें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा।

मिथुन व्यावसायिक योजना सफल होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

कर्क बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रुपए पैसे के लेन-देन में सावधानी रखें। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी।

सिंह पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। आर्थिक दिशा में प्रगति होगी। वाणी की सौम्यता प्रतिष्ठा में वृद्धि करायेगी। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें। धन लाभ के योग हैं।

कन्या जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अनावश्यक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। राजनैतिक दिशा में चल रहा प्रयास सफल होगा।

तुला पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। वाणी की सौम्यता व्यर्थ के विवादों से आपको बचा सकती है। स्वास्थ्य शिथिल रहने की संभावना है। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। नए अनुबन्ध प्राप्त होंगे।

वृश्चिक दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें। आर्थिक प्रयास फलीभूत होंगे। व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अपनों का सहयोग मिलेगा। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें।

धनु व्यावसायिक योजना सफल होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी।

मकर बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। स्थानान्तरण व परिवर्तन की दिशा में किया गया प्रयास सफल होगा। भाई या पड़ोसी का सहयोग मिलेगा। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।

कुम्भ पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें। क्रोध व भावुकता में लिया गया निर्णय कष्टकारी होगा। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

मीन जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। अनावश्यक व्यय का सामना करना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। वाणी की सौम्यता आपको सम्मान दिलायेगी।

कारगर निगरानी तंत्र को मजबूती

शशांक द्विवेदी

एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इसरो ने देश की निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डीआरडीओ द्वारा विकसित 'सिंधु नेत्र' उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया। 'सिंधु नेत्र' उपग्रह हिंद महासागर क्षेत्र में सक्रिय युद्धपोत व व्यावसायिक जहाजों की पहचान करने में सक्षम है। सैटेलाइट ने ग्राउंड सिस्टम के साथ संचार शुरू भी कर दिया है। %सिंधु नेत्र% अपनी तरह का पहला सैटेलाइट है जो चीन के साथ लद्दाख और पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में जमीन पर भी देश की निगरानी क्षमता को बढ़ाएगा। यह भारतीय सीमा के आसपास एलएसी पर चीनी सेना की गतिविधियों पर भी नजर रख सकता है। अगर जरूरत पड़ती है तो सैटेलाइट से दक्षिण चीन सागर से लेकर अदन की खाड़ी में समुद्री लुटेरे वाले क्षेत्र व अफ्रीकी तट पर भी निगरानी की जा सकती है। 'सिंधु नेत्र' को मिलाकर हाल ही में प्रक्षेपित पांच भारतीय उपग्रह भारतीय छात्रों द्वारा निर्मित हैं। इन छोटे उपग्रहों में चेन्नई स्थित स्पेस किड्ज इंडिया द्वारा निर्मित 'सतीश धवन' सैटेलाइट (एसडीसैट) भी शामिल है जो कि तीन उपग्रहों 'यूनिटीसैट' और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह 'सिंधु नेत्र' का संयोजन है। तीन उपग्रहों (यूनिटीसैट) को जेप्पियार इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, श्रीपेरम्बदूर (जेआईटीसैट), जीएच रायसोनी कॉलेज आफ इंजीनियरिंग, नागपुर (जीएचआरसीईसैट) और श्रीशक्ति इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कोयम्बटूर (श्रीशक्ति सैट) के बीच संयुक्त विकास के तहत डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसरो के अनुसार 'यूनिटीसैट का उद्देश्य रेडियो रिले सेवाएं प्रदान करना है।' एसडीसैट एक नैनो उपग्रह है, जिसका उद्देश्य विकिरण स्तर/अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करना और लंबी दूरी की संचार प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करना है। सिंधु नेत्र के सफल प्रक्षेपण से देश की सीमाओं पर घुसपैठ की कोशिश लगभग नामुमकिन हो जाएगी। इसमें लगे खास सेंसरों के चलते सीमापार आतंकियों के जमावड़े की भी सूचना पहले ही मिल जाएगी। साथ ही सीमापार की गतिविधियों का विश्लेषण भी आसान हो जाएगा। यह उपग्रह किसी भी मौसम में बेहद साफ तस्वीरें ले सकेगा। बादलों की मौजूदगी में भी यह दुश्मन की गतिविधियों पर पैनी नजर रखेगा। यही नहीं, इससे आपदा राहत कार्यों में भी भरपूर मदद मिलेगी। इससे रात में भी तस्वीरें ली जा सकती हैं। इसकी मदद से भारतीय सीमाओं की निगरानी और उनकी सुरक्षा को अभेद्य बनाने की प्लानिंग आसान हो जाएगी। डीआरडीओ के अनुसार 'सिंधु नेत्र' उपग्रहों की श्रृंखला में पहला है जो चीन के साथ लद्दाख क्षेत्र और पाकिस्तान के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में भूमि पर अपनी निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगा। यह उपग्रह 3,488 किलोमीटर लम्बी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के सभी भारतीय क्षेत्रों के पास चीनी सेना की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेगा। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को लगता है कि इस तरह के चार और उपग्रह की आवश्यकता है जो दुश्मन की हर चाल पर नजर रखने में मदद कर सकते हैं। दुनिया में बदलते युद्ध के पारंपरिक तौर-तरीके और %मॉडर्न वार% को देखते हुए चीन एवं अमेरिका की तर्ज पर तीनों सेनाओं को एक करने का फैसला लिया गया है। कुल पांच कमांड बननी हैं, जिनमें तीन कमांड्स की अंतरिक्ष से लेकर साइबर स्पेस और जमीनी युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसी क्रम में डिफेंस स्पेस एजेंसी (डीएसए) की स्थापना के साथ-साथ सरकार ने अंतरिक्ष सामग्रियों की क्षमता देखने के लिए डिफेंस स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन भी बनाया है। निकट भविष्य में रक्षा बलों की अंतरिक्ष शाखा को मजबूत किया जाना है। डिफेंस स्पेस एजेंसी का गठन भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं को मिलाकर किया गया है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु (कर्नाटक) में बनाया गया है। इस एजेंसी को भारत के अंतरिक्ष युद्ध और सैटेलाइट इंटेलिजेंस परिसंपत्तियों के संचालन का काम सौंपा गया है। इस एजेंसी को भविष्य में पूर्ण आकार की त्रि-सेवा सैन्य कमान में परिवर्तित किये जाने की उम्मीद है। इस कमांड का नेतृत्व सैन्य बलों के प्रमुख सीडीएस के हाथों में होगा। भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में कम संसाधनों और कम बजट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भविष्य में अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी क्योंकि यह अरबों डालर का मार्केट है। यदि इसी तरह भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे यान अंतरिक्ष यात्रियों को चांद, मंगल या अन्य ग्रहों की सैर करा सकेंगे।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अपने कर्मचारियों का खर्च उठाएगी हैवेल्स इंडिया कंपनी

बिजनेस डेस्क। उपभोक्ता इलेक्ट्रिकल सामान (**Consumer electronic goods**) बनाने वाली कंपनी हैवेल्स इंडिया ने गुरुवार को कहा कि वह भारत में अपने सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्मचारियों के कोरोना वैक्सीनेशन का खर्च उठाएगी। कर्मचारियों का टीकाकरण कराने वाली कंपनियों की संख्या भारत में लगातार बढ़ रही है। अब हैवेल्स भी उनमें से एक बन गई है। हैवेल्स इंडिया लिमिटेड ने एक बयान में कहा कि कंपनी प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया के माध्यम से टीकाकरण कार्यक्रम के तहत भारत में अपने सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्मचारियों के **covid-**19 टीकाकरण की लागत को कवर करेगी। कंपनी के मानव संसाधन कार्यालय प्रमुख वी कृष्णन ने कहा कि जैसा कि हम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, हमारे लिए हमारे लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हैवेल्स के सभी कर्मचारी 'प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष' सरकारी दिशानिर्देशों के तहत दोनों खुराक के लिए लागत का भुगतान कंपनी से प्राप्त करेंगे। इससे पहले इंफोसिस, एसेंचर, कैपजेमिनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीवीएस मोटर कंपनी और रीन्यू पावर सहित कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों व उनके परिवार के सदस्यों के लिए टीका की लागत को कवर करने की प्रतिबद्ध जाहिर की है।

फरवरी में जेएसडब्ल्यू स्टील का क्रूड इस्पात उत्पादन मामूली गिरा

नयी दिल्ली, जेएसडब्ल्यू स्टील का क्रूड इस्पात उत्पादन एक प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ इस साल फरवरी में 13.06 लाख टन (एलटी) पर आ गया। कंपनी ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी। कंपनी देश के शीर्ष छह इस्पात उत्पादकों में से एक है। कंपनी ने पिछले साल इसी महीने में 13.20 एलटी क्रूड स्टील का उत्पादन किया था। इस दौरान, फ्लैट-रोल्ड उत्पादों का उत्पादन भी 9.82 एलटी की तुलना में 6 प्रतिशत गिरकर 9.27 एलटी पर आ गया। हालांकि, फरवरी में लॉन्ग रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन 10 फीसदी बढ़कर 3.40 एलटी हो गया, जो पिछले साल फरवरी में 3.08 एलटी था।

अगली पीढ़ी की स्नैपड्रैगन चिपसेट पर काम कर रहा क्वालकॉम

नई दिल्ली। क्वालकॉम अगली पीढ़ी (नेक्सट जनरेशन) के स्नैपड्रैगन 8सीएक्स चिपसेट पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य एप्पल सिलिकॉन एम1 चिप से मुकाबला करना है। स्नैपड्रैगन 8सीएक्स को सरफेस प्रो एक्स और एआरएम पीसी पर कुछ अन्य हाई-एंड विंडोज 10 पर देखा जाता है। क्वालकॉम ने एक एक्स55 मॉडेम भी शामिल किया है, जिसका मतलब है कि अगली पीढ़ी का 8सीएक्स 5जी एकीकृत मॉडेम के साथ आएगा। एक्सडीएडेवलपर्स की रिपोर्ट के अनुसार, विंडोज के लिए क्वालकॉम की चिपसेट इंटेल, एएमडी, या यहां तक कि एप्पल से मेल नहीं खाती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगली पीढ़ी के स्नैपड्रैगन 8सीएक्स चिपसेट के साथ कंपनी इसे और अधिक शक्तिशाली बनाने की उम्मीद कर रही है। स्नैपड्रैगन एससी8280एक्सपी, दो वेरिएंट में से एक का परीक्षण किया जा रहा है। कथित तौर पर चार हाई-एंड कोर शामिल हैं, जिसे गोल्ड प्लस कहा जाता है और यह 2.7 गीगाहर्ट्ज के साथ चलता है। इन कोर को चार और हाई-एंड कोर के साथ जोड़ा जाता है, जिन्हें 2.43 गीगाहर्ट्ज पर गोल्ड कोर के रूप में जाना जाता है। रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि चिपसेट में एआई आधारित टास्क के लिए एक एकीकृत एनपीयू (न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट) को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, चिपसेट के माध्यम से विंडोज 2-इन-1 और विंडोज पीसी के प्रदर्शन में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने की उम्मीद है।

वैश्विक बाजार में चीनी का दाम बढ़ने से निर्यात में जोरदार इजाफा, 39 लाख टन के हुए सौदे

नई दिल्ली। भारत ने चालू सीजन में अब तक 39 लाख टन चीनी निर्यात करने के सौदे कर लिए हैं जो कि मिलों को आवंटित 60 लाख टन कोटे का 65 फीसदी है। मेक्सिको और अमेरिका समेत दुनिया के कई अन्य देशों में चीनी का उत्पादन इस साल कम होने से वैश्विक बाजार में दाम ऊंचा चल रहा है। दाम ऊंचा होने से भारत को अपनी जरूरत से बाद बाकी बची चीनी को दुनिया के बाजारों में खपाने में मदद मिली है। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चीनी निर्यात के मोर्चे पर इस साल काफी प्रगति देखी जा रही है और चालू शुगर सीजन 2020-21 (अक्टूबर-सितंबर) के अब तक 39 लाख टन तक निर्यात के सौदे हो गए हैं। उन्होंने बताया कि चीनी निर्यात होने से मिलों को गन्ने के दाम का भुगतान करने में सहूलियत मिली है। उद्योग संगठनों से मिली जानकारी के अनुसार, 39 लाख टन निर्यात के जो सौदे हुए हैं उसमें से 18.5 लाख टन चीनी मिलों के गोदामों से उठ चुकी है और 12.5 लाख टन देश के बाहर भी जा चुकी है। भारत ने इंडोनेशिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, यूएई के अलावा अफ्रीका के कई देशों को चीनी निर्यात किया है। देश में सहकारी चीनी मिलों का संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज (एनएफसीएसएफ) के प्रबंध निदेशक प्रकाश नाइकनवरे ने आईएएनएस से कहा, नवंबर से लेकर अप्रैल तक भारत के लिए चीनी निर्यात करने का बेहतर मौका है, क्योंकि इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत को छोड़कर किसी के पास निर्यात करने के लिए चीनी उपलब्ध ही नहीं होती है। ब्राजील की चीनी अप्रैल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आएगी। दुनिया में ब्राजील के बाद भारत ही दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है। नाइकनवरे ने बताया कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम में आई तेजी के बाद ब्राजील चीनी का उत्पादन घटाकर फिर से अपने इथेनॉल उत्पादन कार्यक्रम को बढ़ावा दे सकता है। ऐसे में ब्राजील में चीनी के उत्पादन में कमी आने की संभावना है। साथ ही, थाइलैंड में भी उत्पादन कम रहने की संभावना है।

रिजर्व बैंक ने आईडीबीआई बैंक को पीसीए के दायरे से बाहर किया

मुंबई, रिजर्व बैंक ने बुधवार को आईडीबीआई बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के दायरे से बाहर कर दिया। बैंक के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार आने के बाद करीब चार साल के बाद बैंक को पीसीए से बाहर किया गया है। रिजर्व बैंक ने आईडीबीआई बैंक को मई 2017 में पीसीए व्यवस्था में रखा था। इस व्यवस्था के तहत उन्हें विस्तारित नियामकीय निरीक्षण के तहत कसा जाता है। बैंक ने पूंजी पर्याप्तता, संपत्ति गुणवत्ता के लिये तय सीमा को लांघ लिया था। मार्च 2017 में बैंक का शुद्ध एनपीए 13 प्रतिशत से ऊपर निकल गया था जबकि उसकी संपत्ति पर प्रतिफल और अन्य मानक में भी कमी आई थी। बैंक के कामकाज की 18 फरवरी 2021 को हुई बैठक में समीक्षा की गई। बोर्ड फार फाइनेंसियल सुपरविजन (बीएफएस) ने यह समीक्षा की थी। रिजर्व बैंक ने कहा कि 31 दिसंबर 2020 को समाप्ति तिमाही के बैंक के प्रकाशित परिणामों में यह देखा गया है कि बैंक का कामकाज पीसीए मानकों के दायरे में है। उसका शुद्ध एनपीए, नियामकीय पूंजी मानकों के तय दायरे के भीतर हैं। बैंक ने इस संबंध में लिखित में भी अपनी प्रतिबद्धता जताई है कि वह विभिन्न नियामकीय पूंजी मानकों को बनाये रखेगा और इस संबंध में उसने ढांचागत और प्रणालीगत सुधार पर जोर दिया है।

बाटा इंडिया ने कार्तिक आर्यन को नया ब्रांड एम्बेसेडर बनाया

नयी दिल्ली. प्रमुख फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन को अपना नया ब्रांड एंबेसडर बनाया है। कंपनी ने एक बयान में कहा, ÷बाटा के आधुनिक फैशन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, कार्तिक को बाटा के लोकप्रिय ब्रांडों का प्रचार करते हुए देखा जाएगा। इस सम्बद्धता की शुरुआत बाटा द्वारा चलाये जाने वाले एक नए अभियान से होगी। कार्तिक को टेलीविजन, डिजिटल और अन्य विज्ञापन माध्यमों की एक श्रृंखला में देखा जाएगा।'' बाटा इंडिया लिमिटेड के विपणन विभाग के उपाध्यक्ष, आनंद नारंग ने कहा, हम अपने नए एक्बेसेडर के रूप में कार्तिक आर्यन को शामिल करके खुश हैं।

पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिलाने की मिली मंजूरी, प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय बढेगी

बिजनेस डेस्क।

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग की बीच राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल में मिलाये जाने वाले इथेनॉल की मात्रा 20 फीसदी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इससे पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आने के साथ साथ वाहनों के प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। 8 मार्च को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर ई20 ईंधन के उपयोग को मंजूरी दे दी है।

इन कंपनियों को होगा लाभ

सरकार के इस फैसले का फायदा द्वारिकेश, बलरामपुर चीनी और धामपुर जैसी एथनॉल बनाने वाली कंपनियों को मिलेगा। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि श्व20 वातावरण के लिए भी बेहद सही है है क्योंकि इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन सामान्य पेट्रोल के मुकाबले बेहद कम निकलता है। इस ईंधन के लिए कार और बाइक मैन्यूफैक्चर्स को अलग से बताना होगा कि कौन सा वाहन श्व20 के लिए उपयुक्त है, इसके लिए वाहन में एक स्टीकर भी लगाना होगा। भारत में 2008 से पेट्रोल में ई10 या 10 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित करने की अनुमति है। हालांकि, उपलब्धता की कमी के कारण 6 प्रतिशत से कम इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है।

E20 पेट्रोल के क्या है फायदे

इसके इस्तेमाल करने से पेट्रोलियम पर भारत की निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी।

कार्बन डाई ऑक्साइड (**CO2**) कम निकलेगा तो वातावरण को होने वाला नुकसान भी कम हो जाएगा.

एथनॉल का इस्तेमाल बढ़ने से किसानों को फायदा होगा, उनकी आय बढ़ेगी, क्योंकि एथनॉल गन्ने, मक्का और कई दूसरी फसलों से बनाया जाता है।

एथनॉल काफी किफायती है इसलिए उपभोक्ताओं को भी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

यह देश करते हैं इथेनॉल का उत्पादन

अमेरिका में इथेनॉल का उत्पादन 876 हजार बैरल प्रतिदिन है । उसके बाद ब्राजील है जहां 403 हजार बैरल प्रतिदिन इसका उत्पादन किया जाता है ।

फिर चीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, कोलंबिया, स्पेन है और बेल्जियम जैसा छोटा देश भी है तथा अस्ट्रेलिया के बाद 13 नंबर पर भारत है जो 5.30 हजार बैरल प्रतिदिन उत्पादन करता है। सरकार का कहना है कि वर्तमान समय में जो इथेनॉल का सममिश्रण है वह पूरे देश में 6.2 फीसद है जिसे वर्ष 2022 तक 10 प्रतिशत तथा 2025 20 प्रतिशत करने की योजना है ।

दूरसंचार कंपनियों को केवल सरकारी मंजूरी प्राप्त उपकरणों के ही उपयोग की होगी अनुमति

नयी दिल्ली,

सरकार ने बुधवार को दूरसंचार लाइसेंस नियमों में संशोधन किया। इससे वह बिना भरोसे वाले स्रोतों से नेटवर्क उपकरण लगाये जाने के मामले में नियंत्रण रख सकेगी। लाइसेंस में किये गये संशोधन के अनुसार 15 जून से दूरसंचार परिचालकों को मौजूदा नेटवर्क को उन्नत बनाने, भरोसेमंद उपकरण के रूप में सूचीबद्ध नहीं हो रखे दूरसंचार उपकरण के उपयोग को लेकर राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (एनसीएससी) से मंजूरी लेने की जरूरत होगी। इसके मुताबिक एनसीएससी विशेष प्राधिकरण होगा जो देश की रक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले के आधार पर दूरसंचार उपकरण की खरीद के लिये शर्त लगा सकता है। संशोधन में कहा गया है, ''विशेष प्राधिकरण उन उपकरणों की श्रेणियों को अधिसूचित करेगा जिसके लिये भरोसेमंद स्रोतों से संबंधित सुरक्षा व्यवस्था लागू होती है। उक्त श्रेणियों के उपकरणों के लिये संबधित दूरसंचार उपकरणों के साथ प्राधिकरण भरोसेमंद स्रोतों को अधिसूचित करेगा।'' इससे सरकार को चीन और अन्य ऐसे देशों से उत्पादों की खरीद पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी जिनसे भारत के संबंध बेहतर नहीं हैं। एनसीएससी ऐसे स्रोतों की सूची अधिसूचित कर सकता है, जिससे खरीद नहीं की जा सकेगी।संशोधित अधिसूचना के अनुसार, ''दूरसंचार परिचालक 15 जून, 2021 से अपने नेटवर्क में केवल भरोसेमंद उत्पादों को लगा सकेंगे। साथ ही उन्हें मौजूदा नेटवर्क को उन्नत बनाने के लिये वैसे दूरसंचार उपकरणों के उपयोग को लेकर विशेष प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी, जिन्हें भरोसेमंद उत्पाद के रूप में मान्यता नहीं दी गयी है।'' इसमें कहा गया है, ''हालांकि ये निर्देश जारी सालाना रखरखाव अनुबंधों या मौजूदा उपकरणों को अद्यतन करने को लेकर जारी काम पर लागू नहीं होंगे।'' हालांकि सरकार ने चीनी कंपनियों से उत्पादों की खरीद पर पाबदी नहीं लगायी है, लेकिन उसने सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 में संशोधन किया है ताकि सार्वजनिक खरीद में बोलीदाताओं पर भारत की रक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर उन देशों से खरीद को लेकर पाबंदी लगायी जा सके, जिनकी सीमाएं भारत से मिलती हैं। सार्वजनिक कंपनियों को उन निविदाओं को रद्द करने की जरूरत होगी, अगर पात्र बोलीदाता उन देशों से है, जिनकी सीमाएं भारत से मिलती हैं। इसमें चीन शामिल हैं। सागर एसोसिएट्स के भागीदारी टोनी वर्गीज ने कहा कि दूरसंचार उपकरणों की खरीद को लेकर सरकार द्वारा दूरसंचार लाइसेंस नियमों में संशोधन का कदम 5जी नीलामी को देखते हुए उम्मीद के अनुरूप है। उन्होंने कहा, ''दूरसंचार उपकरण दूरसंचार संपर्क और आंकड़ों के हस्तांतरण के लिहाज से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका देश की सुरक्षा से सीधा संबंध है। इसीलिए इस प्रकार की नीतिगत निर्णय किया गया है...।''

भारत केयर्न के मध्यस्थता अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की प्रक्रिया में: सूत्र

नयी दिल्ली,

भारत केयर्न एनर्जी के पक्ष में आये मध्यस्थता अदालत पैनल के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की प्रक्रिया में है। मध्यस्थता पैनल ने भारत सरकार को ब्रिटेन की तेल कंपनी केयर्न एनर्जी पीएलसी को 1.2 अरब डालर लौटाने को कहा है। सूत्रों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।

सूत्रों ने कहा कि यदि इस मामले में अपील की कार्रवाई शुरू होती है तो भारत को पूरा विश्वास है कि वह मामले को मजबूती से रख सकता है और अपने हितों का बचाव कर सकता है। हालांकि, सूत्र ने इसके साथ ही यह भी कहा कि वह मौजूदा कानूनी व्यवस्था के दायरे में कर विवाद के रचनात्मक निपटान के लिये सकारात्मक रुख रखता है। उन्होंने कहा कि भारत केयर्न मध्यस्थता निर्णय मामले में अपील दायर करने की प्रक्रिया में हैं। सूत्रों ने कहा कि इस मामले में यह पूरी तरह से भारत के अधिकार क्षेत्र में है कि वह दोहरे- कराधान और कर दुरुपयोग की स्थिति में सुधार कर ले।

केयर्न के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिमोन थॉमस ने पिछले महीने वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय से मुलाकात कर मध्यस्थता फैसले पर चर्चा की थी। सूत्रों का

कहना है कि केयर्न को इस चर्चा पर अभी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है।

उनका कहना है कि केयर्न ने इस तरह का कर अपवंचना का ढांचा बनाया है जिसमें उसे भारत में अर्जित आय पर दुनिया में कहीं भी कर नहीं देना पड़े। बहरहाल, एक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने दिसंबर में आम सहमति से यह फैसला दिया कि भारत ने ब्रिटेन-भारत द्विपक्षीय निवेश संधि के तहत 2014 में अपने दायित्व को नहीं निभाया है। भारत के आयकर विभाग ने पिछली तिथि से कर लगाने के कानून के तहत केयर्न पर 10,247 करोड़ रुपये की कर मांग की है।

Moody ने कहा-2022 तक गतिविधियों के Pre-Covid लेवल पर नहीं लौटेंगी अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं

बिजनेस डेस्क।

मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस (**Moody's Investors Service**) ने गुरुवार को कहा कि **covid-**19 के कारण साख में आ रही गिरावट अल्पकालिक होगी लेकिन गतिविधियों के मामले में अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं 2022 तक महामारी से पहले के स्तर पर नहीं पहुंचेंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन (**WHO**) ने पिछले साल 11 मार्च को **covid-**19 को महामारी घोषित किया था। इसके बाद से पूरे साल के दौरान महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में व्यवधान डाला है। इसके साथ ही ऋण में गिरावट और भुगतान में चूक में तेजी आई है। मूडीज ने कोरोना वायरस पर एक वैश्विक रिपोर्ट में कहा कि **covid-**19 से उत्पन्न होने वाली ऋण साख चुनौतियां काफी हद तक हैं, लेकिन इसके अल्पकालिक रहने की संभावना है। जोखिम उन क्षेत्रों के लिए अधिक है, जिनकी सामान्य गतिविधियों पर भी पाबंदियां लगी हुई हैं। मूडीज ने कहा कि 2022 तक अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं महामारी से पहले की गतिविधि के स्तर पर वापस नहीं आ पायएंगी। मूडीज ने कहा कि वह धीमी वैश्विक वापसी और व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण के आसपास अनिश्चितता सामान्य से बहुत अधिक रहने की उम्मीद करता है। उसने कहा कि महामारी के नरम होने के बाद नीतिगत कदमों से आर्थिक गतिविधियों और वित्तीय बाजारों का समर्थन जारी रहेगा। मूडीज ने कहा कि नीति निर्माता लंबे समय तक और कुछ मामलों में कई वर्षों तक आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करते रहेंगे।

मूडीज को उम्मीद है कि इस वर्ष महामारी की व्यापकता और संक्रमण की संख्या धीरे-धीरे कम होगी, क्योंकि टीकाकरण में वृद्धि हो रही है। यह सरकारों को धीरे-धीरे लॉकडाउन संबंधी उपायों को कम करने की सुविधा देगा।

जरूरत के हिसाब से की स्पेक्ट्रम खरीद, प्रतिस्पर्धी होने की मजबूत स्थिति: वोडाफोन आइडिया

नयी दिल्ली,

वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का मानना है कि उसने स्पेक्ट्रम की हालिया नीलामी में कुछ सर्किलों की खाइयों को पाटने के लिये खरीद की है। कंपनी का कहना है कि इससे वह अब बेहतर सेवा तथा ग्राहकों को आकर्षक प्रस्ताव देने के साथ प्रतिस्पर्धी बनने के लिये मजबूत स्थिति में है। कंपनी के मुख्य नियामकीय एवं कॉरपोरेट अफेयर्स अधिकारी पी बालाजी ने इस प्रचलित बात को खारिज करने का प्रयास किया कि वित्तीय दिक्कतों के चलते वोडाफोन आइडिया बड़ी मात्रा में स्पेक्ट्रम नहीं खरीद पायी है।उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा कि कंपनी ने उतने ही स्पेक्ट्रम की खरीद की है, जितने की उसे सेवा व कवरेज में सुधार के लिये आवश्यकता थी। कंपनी के पास ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने और बाजार में प्रतिस्पर्धी होने के लिये पर्याप्त स्पेक्ट्रम हैं। उन्होंने कहा, ''हमने जो चुना उसे खरीदने के लिये चुना, क्योंकि हमारे पास सभी निजी ऑपरेटरों के बीच सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम पूल था ... अब भी, नीलामी के बाद, हम निजी ऑपरेटरों के बीच स्पेक्ट्रम होल्डिंग के मामले में सबसे कम नहीं हैं।'' नीलामी के बाद वोडाफोन आइडिया के पास 1,768.60 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम हैं। बालाजी ने कहा कि कंपनी एकीकरण प्रक्रिया (वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर का विलय) के समय से अपनी व्यावसायिक रणनीति के लिये ईमानदार रही है और सेवा की गुणवत्ता पर केंद्रित रह है, जिसकी पुष्टि तीसरे पक्ष के सत्यापन व बेंचमार्क से भी होती है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने ग्राहकों को मूल्य प्रदान करने वाली साझेदारी की। उन्होंने कहा, ''चाहे वह क्षमता, साझेदारी, कवरेज, ग्राहक अनुभव, सेवा की गुणवत्ता या किसी अन्य बात हो...ये सभी तत्व ठीक हैं। हमारे पास ग्राहकों के लिये एक आकर्षक प्रस्ताव है और हमारे पास बाजार का उचित हिस्सा होगा।''यह पूछे जाने पर कि क्या कंपनी के पास हालिया नीलामी में खरीदे गये स्पेक्ट्रम पर अग्रिम भुगतान करने के लिये पर्याप्त धन है, बालाजी ने कहा, ''हां, हम दूरसंचार विभाग के द्वारा अपेक्षित अग्रिम भुगतान करेंगे।'' उन्होंने कहा, ''11.8 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त है।''

बीमा क्षेत्र में विदेशी हिस्सेदारी की सीमा 74 प्रतिशत करने के कानून संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी

नयी दिल्ली,

केंद्रीय मंत्रिमडल ने बुधवार को बीमा कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी। इससे क्षेत्र में 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का रास्ता साफ हो गया है। फिलहाल, जीवन और साधारण बीमा क्षेत्र में मालिकाना हक और प्रबंधन नियंत्रण भारतीय के पास होने के साथ स्वीकार्य एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत है। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल ने बैठक में बीमा कानून, 1938 में संशोधन को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री निर्मल सीतारमण ने 2021-22 के बजट में कहा था, ''मैं बीमा कंपनियों में एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने और जरूरी सुरक्षा उपायों के साथ विदेशी इकाइयों को मालिकाना हक और नियंत्रण की अनुमति देने के लिये बीमा कानून, 1938 में संशोधन का प्रस्ताव करती हूं।'' इससे पहले, 2015 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत किया गया था। एफडीआई सीमा बढ़ाये जने से

देश में जीवन बीमा की पैठ बढ़ेगी। जीवन बीमा प्रीमियम जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के प्रतिशत के रूप में 3.6 प्रतिशत है जो वैश्विक औसत 7.13 प्रतिशत के मुकाबले कम है।

वहीं साधारण बीमा के मामले में यह जीडीपी का 0.94 प्रतशत है जबकि वैश्विक औसत 2.88 प्रतिशत है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

Sports

बार्सीलोना ने पीएसजी से खेला ड्रॉ, 15 बाद मेस्सी और रोनाल्डों की टीमें नहीं पहुंच पाई क्वार्टर फाइनल

पेरिस ।

पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) ने बार्सीलोना को 1-1 से ड्रॉ पर रोककर चैंपियन्स लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। राउंड आफ 16 का पहले चरण का मुकाबला 4-1 से जीतने वाले पीएसजी ने कुल स्कोर के आधार पर 5-2 से जीत दर्ज की। पीएसजी की ओर से कैंप नाउ में हैट्रिक लगाने वाले काइलान एमबापे ने बुधवार को 31वें मिनट में पेनल्टी पर गोल दागा। बार्सीलोना की ओर से लियोनल मेस्सी ने 37वें मिनट में गोल करके टीम को बराबरी दिलाई। वर्ष 2005 से यह पहला मौका है जब मेस्सी और उनके चिर प्रतिद्वंद्वी क्रिस्टियानो रोनाल्डो में से किसी की भी टीम चैंपियन्स लीग के अंतिम आठ में नहीं पहुंची। रोनाल्डो की यूवेंटस भी मंगलवार को टूर्नामेंट से बाहर हो गई।

टी20 विश्व कप के लिए 'परफेक्ट' संयोजन की तलाश में उतरेगा भारत

अहमदाबाद ।

भारत शुक्रवार से जब यहां इंग्लैंड के खिलाफ पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला में भिड़ेगा तो उसकी नजरें सीरीज जीतने के अलावा अपनी मेजबानी में इस साल होने वाले टी20 विश्व कप के लिए 'परफेक्ट' संयोजन तलाशने पर टिकी होंगी। कप्तान विराट कोहली का मुख्य लक्ष्य इस श्रृंखला के जरिए अक्टूबर में होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप के लिए कोर खिलाड़ियों की पहचान करना होगा। भारतीय कप्तान इसके लिए इयोन मोर्गन की अगुआई वाली दुनिया की नंबर एक टी20 टीम से बेहतर प्रतिद्वंद्वी की उम्मीद नहीं कर सकते। श्रृंखला के दौरान सपाट पिचों पर ढेरों पर बनने की संभावना है और ऐसे में भारतीय गेंदबाजों की राह आसान नहीं होगी। इंग्लैंड के आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने हाल में कहा था कि हमारे लिए यह शानदार मौका है कि हमें उन हालात में खेलने का मौका मिल रहा है जहां हमें विश्व कप खेलना है। भारत के पास हर स्थान के लिए कई विकल्प मौजूद हैं और ऐसे में यह कप्तान के लिए अच्छी खबर है। इस तरह की स्थिति में हालांकि कुछ मुश्किल हालात भी पैदा हो जाते हैं और भारतीय टीम इससे अच्छी तरह वाकिफ है क्योंकि 2019 विश्व कप के दौरान टीम इस तरह की स्थिति का सामना कर चुकी है। उस टूर्नामेंट में भारत के पास नियमित रूप से चौथे नंबर पर खेलने वाला कोई बल्लेबाज नहीं था। पुराने अनुभव को देखते हुए कोहली और मुख्य कोच रवि शास्त्री चाहेंगे कि वे फैसला कर लें कि टी20 विश्व कप में रोहित शर्मा के साथ पारी का आगाज कौन करेगा। इनके पास लोकेश राहुल और शिखर धवन के रूप में दो विकल्प मौजूद हैं। कौशल को देते हुए सीमित ओवरों की अंतिम एकादश में राहुल का चयन लगभग तय है लेकिन वैश्विक प्रतियोगिता में हमेशा धवन ने शानदार प्रदर्शन किया है और वह टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ियों में से एक हैं। कोहली अगर धवन को मौका देने का फैसला करते हैं तो राहुल को चौथे नंबर पर उतरना पड़ सकता है। यह मुश्किल फैसला है जो कोहली को लेना है क्योंकि अगर ये दोनों खेलते हैं तो श्रेयस अय्यर या वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद टीम में जगह बनाने वाले सूर्यकुमार यादव को बाहर बैठना होगा। श्रेयस और सूर्यकुमार चौथे या पांचवें नंबर पर आक्रामक बल्लेबाजी का विकल्प मुहैया कराते हैं और टीम प्रबंधन इसका पूरा फायदा उठाने का प्रयास करेगा। मोटेरा की पिच निश्चित तौर पर सपटा होगी जो खेल के सबसे छोटे प्रारूप की जरूरतों के मुताबिक होगी। दोनों टीमों में कई आक्रामक बल्लेबाज हैं और ऐसे में दर्शकों को ढेरों बाउंड्री देखने को मिल सकती हैं। भारत के पास उप कप्तान रोहित के अलावा ऋषभ पंत और हार्दिक पंड्या जैसे तूफानी बल्लेबाज हैं जबकि इंग्लैंड की टीमें कप्तान इयोन मोर्गन, बेन स्टोक्स, जोस बटलर, डेविड मलान और जेसन रॉय जैसे आक्रामक बल्लेबाज हैं। टी नटराजन के अनुपलब्ध रहने के कारण गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई वापसी करने वाले भुवनेश्वर कुमार करेंगे जबकि सीनियर स्पिनर युजवेंद्र चहल उनका साथ निभाने के लिए मौजूद रहेंगे। इन हालात में स्पिनरों के खिलाफ इंग्लैंड के बल्लेबाजों की कमजोरी को देखते हुए चहल को वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल दोनों का साथ मिल सकता है जिसके बाद शारदुल ठाकुर, दीपक चाहर और नवदीप सैनी में से किसी एक को खेलने का मौका मिलेगा। सीमित ओवरों के प्रारूप में इंग्लैंड को उसके आलराउंडरों से काफी उम्मीदें होंगी और ऐसे में नजरें स्टोक्स, सैम कुरेन और मोईन अली पर टिकी रहेंगी। इंग्लैंड के पास इसके अलावा जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, क्रिस जोर्डन जैसे तेज गेंदबाजों के अलावा कलाई के स्पिनर आदिल राशिद भी हैं जिससे कारण भारत की जीत की राह आसान नहीं होने वाली।

405 दिन बाद टेनिस में फेडरर ने की वापसी, कतर ओपन में जीत के साथ की शुरुआत

दोहा ।

एक साल से अधिक समय तक प्रतिस्पर्धी टेनिस से दूर रहने के बाद दिग्गज खिलाड़ी रोजर फेडरर ने एटीपी टूर पर अपने 24वें सत्र की शुरुआत कतर ओपन में जीत के साथ की। दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी फेडरर ने बुधवार को दूसरे दौर के कड़े मुकाबले में डेन इवान्स को 7-6, 3-6, 7-5 से हराया। आस्ट्रेलिया ओपन 2020 के बाद फेडरर के घुटने की दो सर्जरी हुई और 405 दिन बाद वह पहला मुकाबला खेलने उतरे। फेडरर ने जीत दर्ज करने के बाद कहा कि वापसी करके अच्छा लग रहा है।

मैं जीत दर्ज करूं या हार जाऊं, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं यहां खड़ा हूं। लेकिन बेशक, जीत दर्ज करने से अच्छा महसूस होता है। बीस बार के ग्रैंडस्लैम चैंपियन फेडरर क्वार्टर फाइनल में निकोलोज बासिलाशविली से भिड़ेंगे जिन्होंने मालेक जाजिरी को 6-2, 6-2 से हराया। शीर्ष वरीय डोमीनिक थीम ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए आस्ट्रेलिया ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले अस्लान करात्सेव को 6-7, 6-3, 6-2 से हराया। थीम का सामना अगले दौर में पांचवें वरीय रॉबर्टो बतिस्ता आगुत से होगा जिन्होंने कजाखस्तान के एलेक्सांद्र बुबलिक को 6-4, 6-3 से हराया। तीसरे वरीय आंद्रेय रूबलेव ने रिचर्ड गास्केट के पैर की चोट के कारण मुकाबले से हटने पर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री कोरोना संक्रमित

नई दिल्ली। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान और स्टार स्ट्राइकर सुनील छेत्री ने गुरुवार को कहा कि वह कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं. पॉजिटिव पाए जाने के बाद छेत्री का दुबई में 25 मार्च को ओमान के खिलाफ होने वाले अंतरराष्ट्रीय मैत्री मैच से बाहर होना लगभग तय है. इसी स्थल पर 29 मार्च को संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ मैत्री मैच से भी उनके बाहर रहने की संभावना है. बेंगलुरू एफसी के स्टार फारवर्ड छेत्री ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी और कहा कि वह ठीक महसूस कर रहे हैं. छेत्री ने ट्विटर पर लिखा, 'अच्छी खबर नहीं है, मैं कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया हूं. अच्छी खबर यह है कि मैं ठीक महसूस कर रहा हूं और वायरस से उबर रहा हूं और जल्दी ही फुटबॉल की पिच पर वापसी होनी चाहिए.' पिछले महीने तक गोवा में इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) में जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में हिस्सा ले रहे छेत्री ने कहा, 'सभी को याद दिलाने के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता कि हमेशा की तरह सुरक्षा एहतियात जारी रखें.'छेत्री की बेंगलुरू एफसी की टीम सेमीफाइनल में जगह बनाने में नाकाम रही. टीम लीग चरण के बाद सातवें स्थान पर रही. पूर्व चैंपियन बेंगलुरू एफसी ने पांच मैच जीते जबकि सात ड्रॉ रहे जिससे टीम ने 22 अंक जुटाए. टीम को आठ मैचों में हार का सामना करना पड़ा.छेत्री ने आईएसएल के मौजूदा सत्र में 20 मैचों में आठ गोल दागे.ओमान और यूएई के खिलाफ दो मैचों की तैयारी के लिए राष्ट्रीय टीम के 15 मार्च को दुबई में तैयारी शिविर के लिए एकत्रित होने का कार्यक्रम है. भारत ने पिछला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला नवंबर 2019 में अफगानिस्तान के खिलाफ तजाकिस्तान और ओमान के खिलाफ मस्कट में 2022 फीफा विश्व कप क्वालीफायर के रूप में खेला था.

महिला क्रिकेट

सीरीज में बढ़त लेने उतरेगी भारतीय टीम

महिला क्रिकेट ।

सीरीज में बढ़त लेने उतरेगी भारतीय टीम (प्रीव्यू) 1लखनऊ, 11 मार्च । भारतीय महिला क्रिकेट टीम शुक्रवार को यहां भारत रत्न अटल विहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले तीसरे वनडे मैच को जीतकर पांच मैचों की सीरीज में बढ़त लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। दक्षिण अफ्रीका ने पहले वनडे में भारत को आठ विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी। लेकिन दूसरे वनडे में मेजबान टीम ने बेहतरीन वापसी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को नौ विकेट से हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली है। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे वनडे में पहले बल्लेबाजी करते हुए केवल 157 रनों का ही स्कोर बनाया, जिसे भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना (नाबाद 80) और पूनम राउत (नाबाद 62) के बीच दूसरे विकेट लिए हुई 138 रनों की साझेदारी के दम पर 28.4 ओवर में एक विकेट पर हासिल कर लिया। तीसरे वनडे में भी भारतीय टीम मंधाना से उसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद कर रही होगी। मंधाना दो मैचों में 94.00 की औसत से अब तक 94 रन बना चुकी हैं और वह स्कोररों की लिस्ट में टॉप पर हैं। उनके बाद लारा गुडऑल 89 रनों के साथ दूसरे और और लिजेली ले ने अब तक 87 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने पिछले मैच में 42 रन देकर चार विकेट चटकाए थे और वह दो मैचों में अब तक छह विकेट हासिल कर चुकी है। उनके अलावा दक्षिण अफ्रीका की शबनम इस्माइल चार विकेटों के साथ दूसरे और राजेश्वरी गायकवाड तीन विकेटों के साथ तीसरे नंबर पर हैं।

संक्षिप्त समाचार

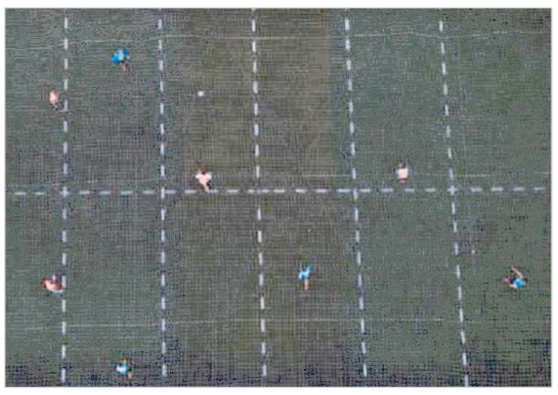

गोवा में मैदानों की देखभाल पर 3 करोड़ से अधिक खर्च किए आईएसएल ने

नयी दिल्ली । इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के आयोजकों ने देश की सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता के 2020-21 के पूरे सत्र के दौरान मैदानों को तैयार रखने के लिए तीन करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। लीग के सातवें सत्र का फाइनल रविवार को एटीके मोहन बागान और मुंबई सिटी एफसी के बीच गोवा के मडगांव में खेला जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण लीग के मौजूदा सत्र का आयोजन गोवा में तीन स्थलों पर किया जा रहा है। आईएसएल ने गुरुवार को विज्ञप्ति में कहा, ''पूरे टूर्नामेंट के दौरान मैदान शीर्ष स्थिति पर रहें इसके लिए लीग ने खर्चे में कोई कमी नहीं की- सत्र के पहले और सत्र के दौरान मैदानों की देखभाल पर तीन करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए। इसमें कहा गया- इन मैदानों को तैयार रखने के लिए 70 मैदानकर्मियों ने दिन-रात काम किया। टूर्नामेंट के आयोजक एफएसडीएल (फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड) के अनुसार इतने कम समय में तीन स्टेडियमों में इतने सारे मैचों के आयोजन के लिए सबसे बड़ी चुनौती खेलने की सतह के स्तर को बनाए रखना था।

विजय हजारे ट्रॉफी : मुंबई ने सेमीफाइनल में कर्नाटक को 72 रन से हराया, पहुंचा फाइनल में

नई दिल्ली ।

शानदार फॉर्म में चल रहे कप्तान पृथ्वी साव के 122 गेंद में 165 रन की मदद से मुंबई ने कर्नाटक को 72 रन से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी एक दिवसीय क्रिकेट चैम्पियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर लिया। मुंबई का सामना रविवार को फिरोजशाह कोटला पर फाइनल में उत्तर प्रदेश से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में उत्तर प्रदेश ने गुजरात को पांच विकेट से हराया। मुंबई ने शॉ की शानदार पारी के दम पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 322 रन बनाए। जवाब में कर्नाटक की टीम 250 रन पर आउट हो गई। शॉ ने कर्नाटक के अनुभवहीन गेंदबाजों पर कोई रहम नहीं दिखाया और टूर्नामेंट में अपना चौथा शतक जड़ डाला। उन्होंने अपनी पारी में 17 चौके और सात छक्के लगाए। इससे पहले उन्होंने दिल्ली के खिलाफ नाबाद 105, पुडुच्चेरी के खिलाफ नाबाद 227 और सौराष्ट्र के खिलाफ नाबाद 185 रन बनाए थे। शॉ के नाम इस टूर्नामेंट में 754 रन हो गए हैं जो राष्ट्रीय वनडे चैम्पियनशिप में एक ही सत्र में सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड है। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (छह) जल्दी आउट हो गए लेकिन साव ने दूसरा छोर संभाले रखा। विकेटकीपर आदित्य तारे (16) के साथ उन्होंने दूसरे विकेट के लिये 71 रन जोड़े। लेग स्पिनर श्रेयस गोपाल ने इस साझेदारी को तोड़ा। शॉ ने अपना लगातार दूसरा शतक सिर्फ 79 गेंद में पूरा किया। शम्स मुलानी ने उनका पूरा साथ देते हुए 45 रन बनाए। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 159 रन जोड़े। कर्नाटक के लिए तेज गेंदबाज वी विशाख ने 56 रन देकर चार विकेट लिए। कर्नाटक के लिए देवदत्त पडीक्कल ने 64 रन बनाए जबकि बी आर शरत ने 61 रन की पारी खेली। इनके अलावा कोई बल्लेबाज नहीं चल सका। मुंबई के लिये तनुष कोटियान और तुषार देशपांडे ने दो दो विकेट लिए।

भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों को ओलंपिक तक 50 हजार रूपए भत्ता मिलेगा

नई दिल्ली

भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीमों के कोर समूह में शामिल खिलाड़ियों को इस साल जुलाई-अगस्त में होने वाले तोक्यो ओलंपिक खेलों तक सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) के तहत 50 हजार रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा। भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) ने बयान में कहा कि मिशन ओलंपिक सेल ने टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम के प्रत्येक सदस्य के लिए 50 हजार रुपये भत्ता स्वीकृत किया है। इस फैसले से 58 हॉकी खिलाड़ियों को फायदा होगा जिसमें 33 पुरुष और 25 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि तोक्यो ओलंपिक खेलों की तैयारी कर रहे पुरुष कोर समूह में शामिल सभी खिलाड़ियों के लिए यह बड़ा प्रोत्साहन है। यह खबर सुनकर हम काफी खुश हैं और सरकार का धन्यवाद देना चाहते हैं। मनप्रीत ने कहा कि हमारे कई खिलाड़ियों की आर्थिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है और इस भत्ते से ओलंपिक खेलों तक वे बिना किसी अड़चन के खेल से जुड़े रह पाएंगे। यह पहली बार है जब टॉप्स के अंतर्गत महिला टीम को भत्ता दिया जा रहा है।

थामस बाक 2025 तक के लिए फिर आईओसी अध्यक्ष नियुक्त

जेनेवा । थामस बाक को बुधवार को चार साल के कार्यकाल के लिये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) का फिर से अध्यक्ष चुना गया और उनका ध्यान इस साल होने वाले तोक्यो खेलों पर होगा। जर्मनी के इस वकील को निर्विरोध चुना गया और उन्होंने 93-1 से जीत हासिल की। चार सदस्यों ने खुद को मतदान से अलग रखा। बाक ने आईओसी सदस्यों की ऑनलाइन बैठक के दौरान कि इस विश्वासमत और भरोसे के लिये तहेदिल से आभार। बाक ने कहा कि तोक्यो ओलंपिक के लिए अब तक का सबसे अच्छा तैयार शहर है। उन्होंने फिर से दोहराया कि कोविड-19 महामारी के दौरान लगाये गये प्रतिबंधों के बावजूद खेल 23 जुलाई को शुरू होंगे। कोविड-19 के कारण ओलंपिक खेलों को एक साल के लिये स्थगित कर दिया गया था और अब भी इनके आयोजन को लेकर आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं।

लेपजिग को हराकर लीवरपूल चैंपियन्स लीग क्वार्टर फाइनल में

बुडापेस्ट । लीवरपूल ने बुधवार को लेपजिग को 2-0 से हराकर चैंपियन्स लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के अंतिम आठ में प्रवेश किया। लीवरपूल की ओर से मोहम्मद सालाह और सादियो माने ने गोल दागे। पहले चरण का मुकाबला भी 2-0 से जीतने वाले लीवरपूल ने कुल स्कोर के आधार पर 4-0 से जीत दर्ज की। हंगरी में तटस्थ स्थान पर हुआ यह मैच लीवरपूल का घरेलू मुकाबला था जिसे पुस्कास एरेना में खेला गया।

रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज वेस्टइंडीज, बांग्लादेश को चाहिए पहली जीत

रायपुर।

वेस्टइंडीज लेजेंडस और बांग्लादेश लेजेंडस शुक्रवार को जब यहां रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टी20 के 12वें मैच में एक-दूसरे से भिड़ेगी, तो उनकी कोशिश इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज करने की होगी। वेस्टइंडीज और बांग्लादेश तालिका में सबसे नीचे क्रमशः छठे और सातवें नंबर पर है और उनके खाते में अभी एक भी अंक नहीं है। तिलकरत्ने की अगुवाई वाली श्रीलंका लेजेंडस पांच मैचों में 16 अंक लेकर पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। उनके बाद सचिन तेंदुलकर के नेतृत्व वाली इंडिया लेजेंडस है, जो एक और मैच जीतते ही सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन जाएगी। बांग्लादेश और वेस्टइंडीज ने अब तक तीन-तीन मुकाबले खेले हैं और दोनों टीमें अपना तीनों मैच हार चुकी हैं। हालांकि वेस्टइंडीज का नेट रन रेट बांग्लादेश से बेहतर है। ब्रायन लारा की अगुवाई वाली वेस्टइंडीज लेजेंडस को अपने पिछले मुकाबले में छह मार्च को श्रीलंका लेजेंडस से पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश ने पिछले दो मैचों में हार के बावजूद अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। मोहम्मद रफीक की कप्तानी वाली टीम वेस्टइंडीज के मुकाबले अधिक संतुलित नजर आ रही है, जबकि लारा की टीम के लिए उसकी गेंदबाजी परेशानी का सबब रही है। कैरेबियाई टीम की बल्लेबाजी उसकी गेंदबाजी से ज्यादा मजबूत है। टीम की गेंदबाजी में निरंतरता के अभाव के साथ साथ गेंदबाजों का फिटनेस भी एक समस्या है। कप्तान लारा ने अपने पिछले मैच में नाबाद अर्धशतक लगाया था, लेकिन इसके बावजूद उसकी बल्लेबाजी ड्वैन स्मिथ पर निर्भर करेगी। गेंदबाजी में टिनो बेस्ट नई गेंद के साथ मोर्चा संभालेंगे। वेस्टइंडीज की तरह ही बांग्लादेश की गेंदबाजी भी एक समस्या रही है। हालांकि कुछ अनुभवी स्पिनरों के माध्यम से टीम रायपुर की धीमी विकेट पर अपना प्रभाव छोड़ सकती है। बांग्लादेश लेजेंडस की बल्लेबाजी ने बेहद प्रभावित किया है, खासकर सलामी बल्लेबाज नजीमुद्दीन ने, जोकि शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ लगाए गए अर्धशक से न केवल उन्हें, बल्कि उनकी टीम को भी आत्मविश्वास मिलेगा। डेथ ओवरों में भी आक्रामक शॉट खेलने के लिए बांग्लादेश के अच्छे खिलाड़ी हैं।

टेनिस खिलाड़ी डेल पोत्रो को टोक्यो ओलंपिक तक फिट होने की उम्मीद

ब्यूनस आयर्स . पूर्व वर्ल्ड नंबर-3 अर्जेंटीना के टेनिस खिलाड़ी जुआन मार्टिन डेल पोत्रो ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक तक वह अपनी चोट से पूरी तरह से उबर जाएंगे। डेल पोत्रो को 2019 में लंदन में एटीपी 500 टूर्नामेंट के दौरान घुटनों की हड्डी में चोट लग गई थी। उन्हें नौ महीने के अंदर दूसरी बार चोट लगी थी और इस कारण वह जून 2019 के बाद से एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल अगस्त में स्विट्जरलैंड में उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ था। डेल पोत्रो ने बुधवार शाम को मीडिया से कहा, मुझे लगता है कि यह मेरा साल है। ओलंपिक खेल मुझे वह प्रेरणा दे रहे हैं जिसकी मुझे जरूरत है। घुटने में मुझे काफी दर्द हो रहा हैं लेकिन मैं अभी अपना करियर खत्म करने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे लगता है कि मेरे पास देने के लिए अधिक है और इसीलिए मैं कोशिश करता रहूंगा। ओलंपिक में टेनिस के मुकाबले 24 जुलाई से एक अगस्त तक खेले जाएंगे। डेल पोत्रो लंदन 2012 ओलंपिक में कांस्य और रियो 2016 ओलंपिक में रजत पदक जीत चुके हैं।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पैराग्लाइडिंग

इंस्ट्रक्टर के लिए भी हैं अवसर

एक पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर का मुख्य काम आम लोगों से लेकर टूरिस्ट को सही तरह से टेनिंग व गाइडेंस प्रदान करते हैं।

आजकल साहसी खेलों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों के मन में पैराग्लाइडिंग के प्रति अलग ही क्रेज देखा जा रहा है, जिसके कारण पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर होना बेहद जरूरी है। एक पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर का मुख्य काम आम लोगों से लेकर टूरिस्ट को सही तरह से टेनिंग व गाइडेंस प्रदान करते हैं। जब भी लोगों की छुट्टियां होती हैं तो वह कुछ अलग और रोमांचक करना चाहते हैं। ऐसे में उनके मन में सबसे पहले पैराग्लाइडिंग करने का ख्याल आता है। जमीन से कई फुट ऊपर उड़ने की चाहत भले ही लोगों के मन में हो, लेकिन इसे बिना इंस्ट्रक्टर की मदद के नहीं किया जा सकता। यह ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं, जो आम लोगों को भी कुछ ही देर में आसमान में उड़ने के लिए टेंड करते हैं। जिस तरह लोगों के मन में कुछ रोमांचक करने की चाहत बढ़ती जा रही हैं, उसके कारण पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर की जरूरत भी काफी अधिक महसूस की जाने लगी है। तो चलिए जानते हैं इस क्षेत्र के बारे में—

क्या होता है काम

आजकल लोगों के मन में पैराग्लाइडिंग के प्रति अलग ही क्रेज देखा जा रहा है, जिसके कारण पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर होना बेहद जरूरी है। एक पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर का मुख्य काम आम लोगों से लेकर टूरिस्ट को सही तरह से टेनिंग व गाइडेंस प्रदान करते हैं। वह उन्हें छोटी से छोटी बारीक बातों की भी जानकारी देते हैं ताकि आम पैराग्लाइडर के साथ कोई अनहोनी घटना न हो। वह ग्राउंड लेवल से लेकर 100 फुट से 1000 फुट तक उंचाई में उड़ने का अभ्यास कराते हैं। कुछ नए पैराग्लाइडर काफी डरते हैं, ऐसे में उनके मन से डर निकालने का काम भी एक पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर का ही होता

लाइब्रेरी साइंस में हैं संभावनाएं

आम तौर पर माना जाता है कि एक लाइब्रेरियन का काम सिर्फ किताबों की सही तरह से व्यवस्था करना है पर यह सही नहीं है। बल्कि लाइब्रेरियन का काम लाइब्रेरी की देखभाल व उसके लिए बजट तैयार करना होता है। इसके अलावा वह किताबों से संबंधित जानकारी व सूचनाओं को भी मुहैया कराता है।

आज के समय में लोग भले ही सूचनाओं को कंप्यूटर या फोन पर हासिल करने लग गए हों, लेकिन फिर भी किताबों का महत्व उसी तरह बरकरार है। आज भी पढ़ने के शौकीन लोग कई तरह की किताबें, मैगजीन व अखबार आदि पढ़ना पसंद करते हैं और इसके लिए वह लाइब्रेरी का रूख करते हैं। वहां पर पत्र—पत्रिकाओं का एक बड़ा कलेक्शन मौजूद होता है और हर कोई अपनी पसंद की किताब वहां आसानी से पढ़ सकता है। अगर आपको हरदम किताबों से घिरे रहना पसंद है तो लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करके बतौर लाइब्रेरियन अपना कॅरियर शुरू कर सकते हैं।

क्या होता है काम

एक लाइब्रेरियन का काम सिर्फ किताबों की सही तरह से व्यवस्था करना ही नहीं होता, बल्कि वह पूरी लाइब्रेरी की देखभाल व उसके लिए बजट तैयार करना होता है। इसके अलावा वह किताबों से संबंधित जानकारी व सूचनाओं को भी मुहैया कराता है। आसान शब्दों में, एक लाइब्रेरी को बेहतर बनाने के लिए जिन भी प्रयासों की आवश्यकता होती है, वह सभी उसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

स्किल्स

इस क्षेत्र में कदम रखने वाले छात्रों को सबसे पहले तो किताबों से लगाव होना बेहद जरूरी है। अगर आपका किताबों के प्रति रूझान नहीं है तो यह क्षेत्र आपके लिए नहीं है। इसके अलावा आपके भीतर मैनेजमेंट स्किल्स भी होने चाहिए। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी उतने ही बेहतर होने चाहिए।

योग्यता

इस क्षेत्र में सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर डिप्लोमा, ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स उपलब्ध हैं। अगर आप लाइब्रेरी साइंस में एक वर्षीय बैचलर डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम स्नातक स्तर की योग्यता होनी बेहद आवश्यक है। ठीक इसी तरह, मास्टर्स डिग्री करने के लिए लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए।

संभावनाएं

अगर आप समझते हैं कि लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करने के बाद आप सिर्फ लाइब्रेरियन ही बन सकते हैं, तो आप गलत है। इस कोर्स को करने के बाद आप इनफॉर्मेशन रिसोर्स स्पेशलिस्ट, रिसर्चर, मेटा—डेटा स्पेशलिस्ट और डॉक्यूमेंट स्पेशलिस्ट के तौर पर भी काम कर सकते

हैं। लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करने के बाद छात्रों को लाइब्रेरी के अलावा, गैलरीज, इंफार्मेशन एंड डाक्यूमेंटेशन सेंटर्स, पब्लिशंगि हाउस आदि में आसानी से काम मिल जाएगा। वैसे आप चाहें तो बतौर रिसर्च कंसल्टेंट भी काम कर सकते हैं।

पैंटिंग के शौक से मिलेगा रोजगार

अगर आप पेंटिंग का शौक रखते हैं और आप को रंगों से खेलना अच्छा लगता है तो आप एक पेंटिंग को अपना पेश बना सकते हैं। अगर आप में कलात्मकता है तो आप इस क्षेत्र में बेहतरीन कॅरियर बना सकते हैं। आज एक पेंटर आर्ट गैलरीज से लेकर अखबर , मैगजीन, पोस्टर, फिल्म व टीवी इंडस्टी में काम कर सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो फ्रीलांस वर्क भी कर सकते हैं या फिर किसी फाइन आर्ट इंस्टीटयूट व कॉलेज में बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। अगर चाहें तो खुद का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं।

बचपन में हम सभी ने अपने हाथों में ब्रश उठाकर पेंटिंग की है। पेंटिंग करना यकीनन हर किसी के मन को सुकून देता है, लेकिन जैसे—जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, वह शौक कहीं पीछे छूटने लगता है। काम की आपाधापी में ब्रश हाथों से कब दूर चला जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर आपको पेंटिंग करना बेहद पसंद है तो क्यों न अपने इसी शौक को आप अपना कॅरियर बना लें। तो चलिए जानते हैं इस क्षेत्र के बारे में—

क्या होता है काम

एक पेंटर कई तरह के काम करता है। उसका काम घर से लेकर बाहर तक हो सकता है। वह सिर्फ छोटे स्केल पर कागज पर पेंटिंग नहीं करता और न की उसका काम सिर्फ कैनवास तक सीमित है, बल्कि वह घर को नया रुप देने के साथ ही किसी या अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी अपना कलात्मकता दिखा समा है।

स्किल्स

इस क्षेत्र में सफलता के लिए सबसे जरूरी है आपका कल्पनाशील होना। इसके अलावा आपको पेंट कलर्स, टोन्स, हाइलाइट व आर्ट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आपको कलर्स के शेड्स व उनकी मिक्सिंग की जानकारी भी होनी चाहिए। कई बार एक पेंटर को कई बड़े प्रोजेक्ट करने होते हैं, इसलिए उसे टीम के साथ भी काम करना होता है। साथ ही आपको कई घंटों तक काम करना पड़ सकता है, इसके लिए आप फिजिकली व मेंटली तैयार रहें। एक पेंटर सिर्फ पेंटिंग ही नहीं करता, बल्कि अपने काम को लोगों के सामने पेश भी करता है, इसलिए आपके कम्युनिकेशन व लैंग्वेज स्किल भी अच्छी होनी जरूरी है।

एक पेंटर बनने के लिए अलग से किसी स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन पेंटिंग की बारीकियों को समझने और अपना हाथ साफ करने के लिए आप इस क्षेत्र में डिप्लोमा या डिग्री कोर्स जैसे बीए इन पेंटिंग, बीए पेंटिंग, स्कल्पचर, अप्लाइड आर्टस, बीएफए पेंटिंग, कोर्स आदि कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद इस क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया जा सकता है।

संभावनाएं

पेंटिंग एक बेहतरीन कॅरियर है और एक पेंटर आर्ट गैलरीज से लेकर न्यूजपेपर, मैगजीन, पोस्टर, फिल्म व टीवी इंडस्टी में आर्टवर्क की तलाश कर सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो फ्रीलांस वर्क भी कर सकते हैं या फिर किसी फाइन आर्ट इंस्टीटयूट व कॉलेज में बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। अगर चाहें तो खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलें।

आमदनी

इस क्षेत्र में आमदनी इस बात पर निर्भर करती है कि आपका काम लोगों को कितना पसंद आता है, लेकिन फिर भी शुरूआती दौर में आप बीस से पच्चीस हजार आसानी से कमा सकते हैं।

वहीं कुछ सालों के अनुभव व आपके काम की लोकप्रियता के आधार पर आपकी आमदनी कई गुना बढ़ भी सकती है।

कैरियर को बनाने में कुछ सहायक बातें

यह ऐसा समय है जबकि एक छोटी सी भूल या गलती आपको कैरियर में काफी पीछे ले जाती है। इसी वजह से कैरियर में हमें अनेक बार ऐसा अहसास होता है कि हम समय से काफी पीछे चले गए हैं। सब कुछ अच्छा होते हुए भी कुछ रह जाने का दर्द हमें सालता रहता है। ऐसे ही अहसास से छुटकारा पाने के लिए जरुरी है कुछ टिप्स अपनाने की वो इस प्रकार हैं।

दक्षता पर ध्यान दें : किसी भी क्षेत्र में दक्षता होनी आवश्यक होती है। हो सकता है कि आप समझाते हों कि आप अपने विभाग में या काम करने की जगह पर सबसे ज्यादा योग्य हैं। आपका अकेडमिक नॉलेज बेहद अच्छा है, लेकिन जब तक काम में दक्षता नहीं होगी यह सब बेकार हो जाता है। इसके लिए जरुरी है कि किताबी ज्ञान से इतर करके देखने पर अमल किया जाए। अपनी कार्य और प्रोफाइल के मुताबिक अपने आपको और अधि क दक्ष बनाएं ताकि आपकी रुकावटें दूर हो सकें और कैरियर बेहतर हो सके।

खुद को बदलने में है समझदारी : अनेक बार हम एक ही जगह लंबे समय तक एक ही तरह का काम करते हुए स्वयं को संतुष्ट कर लेते हैं। यह आपके कैरियर के लिए हानिकारक बात हो सकती है। एक ही जगह या एक ही कंपनी में रहना ठीक है, लेकिन कुछ नया न सीखना या न करना खुद को जांचने और परखने की बजाय जंग लगाने के बराबर है। इसलिए खुद को अप टू डेट रखने के लिए कुछ जरुरी बदलाव लाएं। नई-नई तकनीक और नए नए हुनर सीखने में कोई हर्ज नहीं है।

आत्मविश्वास लाएं : अब आप भले ही योग्य और सीखे हुए हैं लेकिन इसके साथ जरुरी है कि आप में आत्मविश्वास भी हो। काफी अच्छी शि क्षा और आपका कई मायनों में दूसरों से बेहतर होना तब फायदेमंद नहीं होता जबकि आपमें आत्मविश्वास नहीं होता। ऐसे में यह सब बेकार साबित हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि अपने अंदर आत्मविश्वास जगाएं। जरा सोचें कि जब आप आत्मविश्वास से भरे होंगे तभी तो दूसरे आपकी बात पर विश्वास करेंगे।

ईमानदारी जरुर रखें : तमाम बातों के साथ ही साथ आप अपने करियर के प्रति ईमानदार रहें, वर्ना एक छोटा सा झूठ आपके कैरियर में ग्रहण लगा सकता है। कभी भी खुद को लेकर बड़ी-बड़ी बातें न करें। ऐसा करने से लोगों को या आपके बॉस को आपसे उम्मीदें बढ़ती चली जाएंगी और तब जबकि आप उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे तो यह आपके कैरियर में बैरियर लगाने वाला साबित हो जाएगा। इसलिए अपने काम को बोलने दें और खुद भी ईमानदार रहें।

अतिमहत्वाकांक्षा से बचें: महत्वकांक्षी तो प्रत्येक मनुष्य को होना ही चाहिए, लेकिन अपनी महत्वकांक्षाओं के लिए अगर आप दूसरों को किनारे करेंगे तो यह आपके लिए कुछ समय तक तो सुकून या संतोष देने वाला साबित हो सकता है, लेकिन करियर को ऊंची उड़ान भरने में सहायक साबित नहीं हो सकता। इसलिए महत्वकांक्षी होना अच्छा है, लेकिन अतिमहत्वाकांक्षी होकर गलत कदम उठाना सही नहीं है।

क्रांति समय

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

कोरोना

देश के छह राज्यों में कोरोना प्रकोप की हिस्सेदारी 85.91 प्रतिशतः स्वास्थ्य मंत्रालय

नई दिल्ली।

देश में घातक वायरस कोरोना का कहर एक बार फिर सिर उठाने लगा है। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु से लगातार वायरस संक्रमण के ज्यादा मामले आ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में देश में सामने आए कुल मामलों में इन छह राज्यों की हिस्सेदारी 85.91 प्रतिशत रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को इस बारे में बताया। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 22,854 मामले आये। मंत्रालय के अनुसार नये मामलों में सबसे अधिक 13,659 मामले (देश में कुल मामलों का करीब 60 प्रतिशत) महाराष्ट्र से है। इसके बाद केरल (2,475) और पंजाब (1,393) से मामले सामने आए हैं। आठ राज्यों- महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा में नए मामलों में वृद्धि हो रही है।

भारत में वर्तमान में 1,89,226 मरीजों का उपचार चल रहा है जो कुल मामलों का 1.68 प्रतिशत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में परिवर्तन देखा जा रहा है और केरल में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट तथा महाराष्ट्र में बढ़ोतरी देखी गई है। मंत्रालय ने गुरुवार सुबह सात बजे अनंतिम रिपोर्ट जारी कर बताया कि देश में अब तक 4,78,168 सत्रों के माध्यम से 2.56 करोड़ (2,56,85,011) से अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ है। टीका लेने वालों में 71,97,100 स्वास्थ्यकर्मियों को पहली खुराक, 40,13,249 स्वास्थ्यकर्मियों को दूसरी खुराक, 70,54,659 अग्रिम मोर्चा के कर्मियों को पहली खुराक और 6,37,281 अग्रिम मोर्चा के कर्मियों को दूसरी खुराक दी गयी। इसके अलावा गंभीर बीमारी से पीड़ित 45 साल से अधिक उम्र के 9,67,058 लोगों को तथा 60 साल से अधिक उम्र के 58,15,664 लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई। टीकाकरण अभियान के 54वें दिन (10 मार्च) कुल 13,17,357 लोगों को टीके की खुराक दी गई। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से कुल 126 लोगों ने दम तोड़ा हैं मंत्रालय ने बताया कि मौत के नए मामलों में 82.54 प्रतिशत मामले छह राज्यों से हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 54 लोगों की मौत हुई। इसके बाद पंजाब में 17 और केरल में 14 लोगों की मौत हुई। देश में पिछले 24 घंटे में 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों - गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा, गोवा, झारखंड, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, सिक्किम, लद्दाख, मणिपुर, दमन एवं दीव और दादर एवं नगर हवेली, मेघालय, मिजोरम, नगालैड, त्रिपुरा और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा अरुणाचल प्रदेश में कोविड-19 से किसी की मौत नहीं हुई।

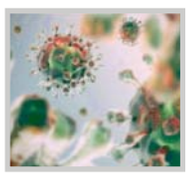

पीएम मोदी की मां, महाराष्ट्र के सीएम और बंगाल के गर्वनर ने ली कोरोना की पहली खुराक

नई दिल्ली।

जानलेवा वायरस कोरोना से रोकथाम के लिए ईजाद स्वदेशी टीके की पहली खुराक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मां हीरा बा ने गुरुवार को ली और अपना टीकाकरण करवाया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं ट्वीट कर यह जानकारी साझा की और सभी से टीके के लिए पात्र लोगों के टीकाकरण में मदद करने की अपील की। उन्होंने ट्वीट किया, 'यह जानकारी साझा करते हुए मुझे खुशी हो रही है मेरी मां ने आज कोविड-19 टीके की पहली खुराक ली। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे सभी पात्र लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें और उनकी सहयता करें।' हीरा बा गुजरात में रहती हैं। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी कोरोना का टीका लगवाया है। ठाकरे ने मुंबई के जेजे अस्पताल जबकि धनखड़ ने कोलकाता के कमांड हॉस्पिटल में वैक्सीन की पहली डोज ली। ध्यान रहे कि पिछले वर्ष आज ही के दिन 11 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूचओ) ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया था। सालभर बाद भारत में कोरोना फिर से डराने लगा है। देश में फरवरी के मुकाबले मार्च महीने में नए दोगुने की संख्या में नए कोरोना केस आने लगे। बुधवार को पूरे दिन कुल 22,854 नए कोविड मामलों का पता चला जबकि इस महामारी से और 126 लोगों की मौत हो गई।

अब देश में कुल कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 1,12,85,561 हो गई है जबकि इस

महामारी ने अब तक भारत में 1,58,189 जिंदगियां काल की ग्रास बन गईं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि अभी देश में कुल 1,89,226 सक्रिय कोरोना केस हैं जबकि इलाज के बाद ठीक हुए मरीजों की कुल संख्या 1,09,38,146 है।

महाराष्ट्र में लॉकडाउन पर 2-3 दिन में फैसला- मुख्यमंत्री

मुंबई। महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन का फैसला लिया जा सकता है. राज्य के मख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि लॉकडाउन लगाने का फैसला दो-तीन दिन के भीतर लिया जा सकता है. दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना अब बेकाबू होने लगा है. सरकार के तमाम कोशिशों के बाद भी यहां कोरोना महामारी का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है. बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के इस साल एक दिन में सबसे अधिक 13,659 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 22,52,057 हो गई. जबकि 54 और रोगियों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या 52,610 हो गई है. इसके बाद ही अब माना जा रहा है कि लॉकडाउन के फैसले को टाल रही उद्धव सरकार अब निर्णय ले सकती है. बता दें कि पहले ही इस बात की हिदायत दी गई थी कि अगर केस बढ़ेंगे तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया जा सकता है. इस बीच महाराष्ट्र में हर रोज आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं वहीं अधिकांश लोग भी पूरी तरह से लापरवाह बने हुए हैं. केंद्र सरकार ने भी कहा था कि महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामले बढ़ने का कारण महामारी के प्रति लोगों की कम जागरूकता और डर की कमी है.

केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई से खुलेंगे, ऊखीमठ के ओम्कारेश्वर मंदिर से हुई घोषणा

केदारनाथ । देव भूमि उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई को सुबह पांच बजे से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वेदपाठियों और तीर्थपुरोहितों ने पूजा पाठ के बाद शुभ मुहर्त निकाला है। ऊखीमठ के ओम्कारेश्वर मंदिर से हुई बाबा केदार के कपाट खुलने की घोषणा हुई है। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने के लिए 13 मई को भगवान भैरवनाथ की पूजा-अर्चना की जाएगी। इसके बाद 14 मई को बाबा केदार की डोली फाटा में विश्राम करेगी जिसने ऊखीमठ से प्रस्थान किया था। 15 मई को यह डोली गौरीकुंड और 16 मई को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। 17 मई को सुबह पांच बजे भगवान केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। आपको बता दें कि केदारनाथ समेत चारधामों के कपाट हर साल अक्टूबर-नवंबर में सर्दियों में बंद कर दिए जाते हैं, जो अगले साल फिर अप्रैल-मई में भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। गढ़वाल हिमालय में स्थित बदरीनाथ धाम के कपाट 18 मई से श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। गौरतलब है कि बदरीनाथ के कपाट खोले जाने के लिए शुभ मुहूर्त का ऐलान मंगलवार को बसंत पंचमी के मौके किया गया था। यह शुभ मुहूर्त नरेंद्रनगर स्थित टिहरी राजवंश के दरबार में आयोजित एक समारोह के दौरान निकाला गया था।

ममता पर हुए हमले पर बोली साध्वी- सुरक्षा घेरे में किसी का घुसकर हमला करना समझ से परे

फतेहपुर-

यूपी के फतेहपुर जिले में एक दिवसीय दौरे में आई केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने ममता बनर्जी पर हुए हमले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा घेरे में किसी का घुसना और हमला करना यह समझ से परे है, अगर ऐसा हुआ है तो ममता को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी हर हथकंडे अपनाती हैं, मुख्यमंत्री की इतनी सिक्योरिटी होती है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री उसके बाद भी कोई हमला कर दे तो मुख्यमंत्री अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती तो बंगाल के लोगों का क्या सुरक्षा करेंगे। यह घटना ममता जी का षड्तंत्र है, क्योंकि वहां से हारती हुई दिख रही हैं। मुख्यमंत्री की बहुत कड़ी सुरक्षा होती है, सुरक्षा में किसी का घुसना और हमला करना यह समझ से परे है अगर ऐसा हुआ है तो ममता को इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनाव आयोग से शिकायत करना उनका अधिकार है। हमारे लोगों ने मांग किया है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए।

असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित किए 2 और उम्मीदवार के नाम

डिब्रूगढ़।

असम में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को अपने दो और उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं. इसमें बोखाजान से रतन इंग्टी और दीफू से सम रोंगहांग चुनाव लड़ेंगे. ये दोनों सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं. 126 सदस्यीय असम विधानसभा के लिए अब तक कांग्रेस 68 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है. यहां पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है. इससे पहले बुधवार को पार्टी ने 26 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी. साथ ही यहां के चुनावों के लिए वरिष्ठ नेताओं मोहन प्रकाश और जयदेव जेना को विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया था. 7 मार्च को अपनी पहली सूची में कांग्रेस ने 40 नामों को जारी किया था. इसमें अहम उम्मीदवार प्रद्युत कुमार भुइयां हैं जो नलबाड़ी से चुनाव लड़ेंगे. वहीं मिस्बाहुल इस्लाम लस्कर बोरखोला से अपनी किस्मत आजमाएंगे. कांग्रेस विधायक दल के नेता देवव्रत सैकिया नाजिरा सीट से मैदान में हैं और पूर्व मंत्री रकीबुल हुसैन समागरी से चुनाव लड़ेंगे. पार्टी ने गोहपुर से असम कांग्रेस प्रमुख रिपुन बोरा, बरचल्ला से राम प्रसाद शर्मा और तेजपुर से अनुज कुमार मच को उम्मीदवार बनाया है. इसके अलावा पार्टी ने खुमताई से बिस्मार्क गोगोई और जोरहाट से राणा गोस्वामी को मैदान में उतारा है. असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से 8 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए और 16 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं. बता दें कि असम में तीन चरणों में चुनाव होने हैं.

टिकट बटवारे से नाराज महिला कांग्रेस नेता

पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष मोहन देव की बेटी सुष्मिता देव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. हालांकि, गुवाहाटी और दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने रिपोर्ट का जोरदार खंडन किया. देव के करीबी लोगों के अनुसार, वह सिलचर में एआईयूडीएफ को सीट आवंटन से परेशान हैं और इसके अलावा वह दक्षिणी असम में बंगाली बहुल क्षेत्र के उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी नाराज हैं.

तीन चरणों में होगा असम विधानसभा चुनाव

आपको बता दें कि असम में 27 मार्च से 6 अप्रैल के बीच तीन चरणों में मतदान संपन्न होगा, पहले चरण के तहत राज्य की 47 विधानसभा सीटों पर 27 मार्च को, दूसरे चरण के तहत 39 विधानसभा सीटों पर एक अप्रैल और तीसरे व अंतिम चरण के तहत 40 विधानसभा सीटों पर छह अप्रैल को मतदान संपन्न होगा. नामांकन की आखिरी तारीख नौ मार्च है.

यूपी- जो गुनाह नहीं किया उस जुर्म में काटे 20 साल, अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

- ऐसे पीड़ितों को मुआवजा के लिए बनाई जाए गाइडलाइंस

नई दिल्ली। उसने जो गुनाह नहीं किया उसकी सजा में 20 साल की कैद काटी। ऐसे ही फर्जी केस में फंसाने के मामले में इस पीड़ित को मुआवजा दिए जाने के लिए दिशानिर्देश बनाने के लिए देश की शीर्ष कोर्ट से अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी के विष्णु तिवारी केस का हवाला दिया गया जिन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी करते हुए कहा कि उन्हें आपसी झगड़े के कारण रेप और एससी/एसटी केस में फंसाया गया। वह 20 साल जेल में रहे।

सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाए कि वह ऐसे पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए गाइडलाइंस तैयार करें और इस बाबत लॉ कमिशन की रिपोर्ट को लागू करें।

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारों को प्रतिवादी बनाते हुए ऐडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद-32 के तहत रिट याचिका दायर की गई है और कहा गया है कि यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विष्णु तिवारी को 28 जनवरी 2021 को बरी किया था। विष्णु 20 साल जेल में बंद रहा था। उस पर रेप और एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अपने फैसले में कहा कि विष्णु तिवारी को जमीन विवाद के कारण रेप और जातिसूचक शब्द कहने के मामले में फंसाया गया था। अपनी अर्जी में याचिकाकर्ता ने कहा कि विष्णु तिवारी जैसे विक्टिम को मुआवजा दिए जाने के लिए गाइडलाइंस की जरूरत है। इसके लिए लॉ कमिशन की 277 रिपोर्ट को लागू किया जाए। ऐसे विक्टिम जिन्हें फर्जी केस में फंसाया जाता है उनको मुआवजा देने के लिए गाइडलाइंस बनाए जाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए और राज्यों को निर्देश दिया जाए कि वह गाइडलाइंस का पालन करें।

याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का कस्टोडियन है और वह नागरिकों की लाइफ और लिबर्टी का संरक्षक है। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वह गाइडलाइंस बनाने के लिए निर्देश जारी करे, जिन्हें फर्जी केसों में फंसाया जाता है। उनके मुआवजे के लिए कोई भी कानूनी मैकेनिज्म नहीं है। इस कारण विक्टिम के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे विक्टिम के समानता का अधिकार और जीवन व लिबर्टी के अधिकारों का हनन हो रहा है।

नंदीग्राम घटना

नंदीग्राम घटना को लेकर चुनाव आयोग से मिला टीएमसी प्रतिनिधिमंडल

नेशनल डेस्कः

नदीग्राम में बुधवार को ममता बनर्जी के साथ हुई दुर्घटना को लेकर टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। टीएमसी ने चुनाव आयोग की निंदा करते हुए कहा कि ईसी सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम साबित हुआ है। टीएमसी ने कहा कि आयोग अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता, क्योंकि विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद वही कानून-व्यवस्था की स्थिति के लिए जिम्मेदार है। तृणमूल नेताओं ने दावा किया कि यह हमला ''तृणमूल सुप्रीमो की जान लेने का गहरा षड्यंत्र था''। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पड़ोसी राज्यों से असामाजिक तत्वों को हिंसा करने के लिए नंदीग्राम भेजा था। तृणमूल के प्रतिनिधि मंडल ने यहां आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद निर्वाचन आयोग पर भाजपा नेताओं के ''आदेशानुसार'' काम करने का आरोप लगाया और कहा कि ''बनर्जी पर हमला हो सकने की रिपोर्ट के बावजूद निर्वाचन आयोग ने कुछ नहीं किया।'' इस बीच, भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने यहां ईसी अधिकारियों से मुलाकात की और बनर्जी पर हमले की घटना की संपूर्ण जांच कराए जाने की मांग की। तृणमूल महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा, ''बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति अच्छी थी, लेकिन चुनावों की घोषणा के बाद कानून-व्यवस्था ईसी (निर्वाचन आयोग) की जिम्मेदारी बन गई।'' उन्होंने कहा, ''ईसी ने राज्य पुलिस के डीजीपी को हटा दिया और अगले ही दिन उन पर(बनर्जी) हमला हो गया। निर्वाचन आयोग ने वीरेंद्र को पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक पद से तत्काल प्रभाव से हटाने का मंगलवार को आदेश दिया था और उनकी जगह पी नीरजनयन को नियुक्त किया था। चटर्जी ने दावा किया कि वरिष्ठ भाजपा नेताओं के कई बयानों से ये पर्याप्त संकेत मिले थे कि बनर्जी पर हमला हो सकता है और ''ये जानकारियां होने के बावजूद मुख्यमंत्री को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई।'' उन्होंने कहा, ''जब ईसी प्रशासन का प्रभारी है, तो ममता बनर्जी पर हमले की जिम्मेदारी कौन लेगा? ईसी को इस घटना की जिम्मेदारी लेनी होगी। चटर्जी ने कहा, ''वे भाजपा नेताओं के आदेश पर काम कर रहे हैं। भाजपा ने ईसी से किसी अधिकारी को हटाने को कहा और वे उसे हटा रहे हैं।'' इससे पहले, राज्य के मंत्री चटर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और मामले में शिकायत दर्ज कराई। प्रतिनिधि मंडल ने मामले की संपूर्ण जांच कराए जाने की मांग की। चटर्जी के साथ राज्य की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य और राज्यसभा में तृणमूल के नेता डेरेक ओब्रायन भी निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मिले। ओ ''ब्रायन ने कहा, ''आपको घटनाक्रम को समझना होगा।

संक्षिप्त समाचार

कानपुर सामूहिक दुष्कर्म मामले में कांग्रेस ने न्यायिक जांच की मांग उठाई, कहा- सीएम योगी इस्तीफा दें

कानपुर।

यूपी में बढती दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने चिंता जताई है। कानपुर में एक नाबालिग बच्ची के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म और फिर उसके पिता की सड़क हादसे में मौत के मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। पार्टी ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफे की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यह आरोप भी लगाया कि भाजपा शासित प्रदेशों में महिला विरोधी अपराध की घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी चुप्पी साध लेते हैं। उल्लेखनीय है कि कानपुर के घाटमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर एक बलात्कार पीड़िता के पिता की बुधवार को कथित तौर पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल टेक्स चल रहा था, उसी दौरान यह घटना हुई। वहीं, परिजनों ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया है कि पीड़िता के पिता को साजिश के तहत दुर्घटना में मारा गया। सुप्रिया ने संवाददाताओं से कहा, 'उत्तर प्रदेश में महिला विरोधी अपराध की घटना थमने का नाम नहीं ले रही हैं। 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की दिल दहलाने की घटना हुई है। महिला विरोधी अपराध पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी नहीं बोलते। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री भी चुप्पी साध लेती हैं।' उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में जाकर उस प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की बात करते हैं। हमारा उनसे सवाल है कि क्या आपने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बना दिया? यहां के अपराधों पर तो उनके मुंह में दही जम जाती है।' सुप्रिया ने कहा, 'अगर मुख्यमंत्री में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों के लिए पद से इस्तीफा देना चाहिए।' उन्होंने कानपुर की घटना को लेकर कहा, 'इस मामले की न्यायिक जांच हो, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए तथा दोषियों और उनको संरक्षण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो।'

आयकर विभाग की कोलकाता में छापेमारी, 1.21 करोड़ रुपये की नकदी जब्त

नई दिल्ली।

आयकर विभाग ने कोलकाता में दो लोगों के खिलाफ छापामार कार्रवाई करके बिना लेखा-जोखा वाली 1.21 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की।केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बताया कि पश्चिम बंगाल की राजधानी में दो लोग ''कमीशन लेकर दूसरों की नकदी का प्रबंधन करते थे।''बोर्ड ने कहा, खुफिया विभाग द्वारा एकत्र की गई सूचना के आधार पर छापामार कार्रवाई की गई। कुल 121.50 लाख की नकदी जब्त की गई। पश्चिम बंगाल में 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होगा।

तिहाड़ से जुड़ रहे एंटीलिया के बाहर कार में मिली जिलेटिन छड़ों के तार

-मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस को दी जानकारी, दिल्ली स्पेशल सेल टीम पहुंची तिहाड़

नई दिल्ली।

देश के उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर एसयूवी कार में मिली विस्फोटक जिलेटिन की छड़ों के तार दिल्ली की तिहाड़ जेल से जुड़ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि जिस टेलीग्राम का इस्तेमाल जैश उल हिंद ने किया है वो तिहाड़ जेल में बनाया गया था। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिख कर बताया था कि जिस टेलीग्राम एप से जैश उल हिंद ने जिलेटिन रखने की जिम्मेदारी ली थी वह तिहाड़ जेल में बना था। सुरक्षा एजेंसियों ने उसे ट्रैक कर लिया है। दिल्ली में स्पेशल सेल ने जब जांच की तब मुंबई पुलिस की जानकारी सही निकली। स्पेशल सेल की टीम तिहाड़ जाकर वहां बंद आतंकियों से इस बारे में जानकारी प्राप्त कर रही है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के बाहर 25 फरवरी की शाम को विस्फोटक सामग्री वाली खड़ी स्कॉर्पियो कार मिली थी। इस मामले में जांच की जिम्मेदारी 9 मार्च को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपी गई थी।

केंद्र की निजीकरण के जरिए 5 लाख करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा करने की योजना

नई दिल्ली।

केंद्र सरकार ने निजीकरण के जरिए 5 लाख करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा करने की योजना बनाई। दरअसल, मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने के लिए यह कदम उठा रही है। इसी के अंकर्गत साल अगले चार साल में निजीकरण के जरिए 5 लाख करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए 100 सरकारी संपत्तियों की सूची बना ली है। इसी हफ्ते एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर आयोजित एक वर्कशॉप में निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) ने मंत्रालयों और राज्य सरकारों से अपील की कि वह इस प्रक्रिया में तेजी लाए। एक अंग्रेजी अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र ने अगले चार साल में (2025 तक) निजीकरण के जरिए 5 लाख करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा करने की योजना बनाई है। इसके लिए नीति आयोग ने 100 महत्वपूर्ण सरकारी संपत्ति की पहचान भी कर ली है। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने साल 2025 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कोरोना के कारण देश की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में चली गई, सरकार की कमाई को भारी चोट पहुंची है, इसके इसके बावजूद सरकार अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटी है। रिपोर्ट के मुताबिक, नीति आयोग ने अलग-अलग मंत्रालयों से कहा है कि वे निजीकरण करने लायक संपत्ति की पहचान करें। नीति आयोग ने निजीकरण की दिशा में सरकार को तेजी से बढ़ने का सुझाव दिया है। इसलिए तमाम प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारी शुरू करने का निर्देश जारी किया गया है। 10 अलग-अलग मंत्रालयों और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की 31 महत्वपूर्ण संपत्तियों की पहचान की जा चुकी है और इसकी लिस्ट भी संबंधित मंत्रालयों को सौंपी जा चुकी है। इन सरकारी संपत्तियों में टोल रोड, पोर्ट, क्रूज टर्मिनल, टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, ट्रांसमिशन टॉवर, रेलवे स्टेशन, स्पोर्ट्स स्टेडियम, माउंटेन रेलवे, ऑपरेशनल मेट्रो सेक्शन, वेयरहाउसेस और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स शामिल हैं।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक : सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफ़सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास , (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत
गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक :सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/751000 (Subject to Surat jurisdiction)